GUPTA CLASSES

करेंट अफेयर्स

जनवरी-2022

हिन्दी

भाग-1

GUPTA CLASSES

Current Affairs Study PDF – January 2024

Current Affairs for Competitive Exam

Table of Contents

NATIONAL AFFAIRS 7

CABINET APPROVALS 7

PARLIAMENT 14

LAUNCHES & INAUGURATION 16

FESTIVAL 285

OTHER NEWS 296

STATE NEWS 56

GOVT SCHEMES 61

INTERNATIONAL AFFAIRS 67

VISITS 72

INDIAN VISITS 72

FOREIGN VISITS 79

BANKING & FINANCE NEWS 84

BANKING NEWS 84

RBI IN NEWS 84

SEBI 97

AGREEMENTS & MoUs SIGNED 100

OTHER BANK NEWS 108

FINANCE NEWS 121

ECONOMY & BUSINESS NEWS 1305

MoU's & AGREEMENTS 1382

COMMITTEES & MEETINGS 1568

SUMMITS, EVENTS & CONFERENCE 1589

INDEX 1743

RANKING 1743

REPORTS 18563

AWARDS & RECOGNITIONS 197

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS 204

ACQUISITION & MERGERS 25020

SCIENCE & TECHNOLOGY 25524

DEFENCE 25644

EXERCISE 27744

TESTING 2839

OTHER DEFENCE NEWS 2851

SPORTS 28954

OBITUARY 30063

BOOKS & AUTHORS 30770

IMPORTANT DAYS 3103

APPS & WEB PORTAL 33291

ENVIRONMENT 3408

NATIONAL AFFAIRS

CABINET APPROVALS

5 जनवरी 2024 को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है,

i.मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना "PRITHvi VIgyan (PRITHVI)" को मंजूरी दी

ii.मंत्रिमंडल ने संयुक्त लघु उपग्रह के विकास पर सहयोग से संबंधित ISRO और MRIC के बीच MoU को मंजूरी दी

iii.मंत्रिमंडल ने अभियान शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का समर्थन करने के लिए USAID/भारत के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।

iv.मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दी & इसका नाम "महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम" रखा।

v.मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और गुयाना के बीच MoU पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना "PRITHvi VIgyan (PRITHVI)" को मंजूरी दी

PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **4,797 करोड़ रुपये** के कुल परिव्यय के साथ MoES की व्यापक योजना "PRITHvi VIgyan (**PRITHVI**)" को मंजूरी दे दी है। यह योजना **2021 से 2026** की अवधि के दौरान लागू की जाएगी।

PRITHVI योजना:

PRITHvi, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, प्रौद्योगिकी & मानव संसाधन विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने का संक्षिप्त रूप है। यह योजना पृथ्वी प्रणाली के 5 घटकों (वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, निम्नतापमंडल और जीवमंडल) को संबोधित करेगी ताकि पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की समझ में सुधार किया जा सके और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की जा सकें।

उद्देश्य:

i.वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, निम्नतापमंडल और ठोस पृथ्वी पर दीर्घकालिक अवलोकन करना।

ii.मौसम, महासागर और जलवायु खतरों को समझने और भविष्यवाणी करने के लिए प्रतिमान प्रणाली का विकास करना।

iii.पृथ्वी के ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों का अन्वेषण करना।

iv.सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्री संसाधनों की खोज और टिकाऊ दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना।

v.सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के लिए ज्ञान का सेवाओं में अनुवाद करना।

PRITHVI योजना के बारे में:

PRITHVI में 5 चल रही उप-योजनाएँ शामिल हैं जो समाज के लिए विज्ञान को सेवाओं में परिवर्तित करने के लिए शुरू की गई हैं।

i.वायुमंडल & जलवायु अनुसंधान-प्रतिमान अवलोकन प्रणाली & सेवाएँ (ACROSS)

ii.महासागर सेवाएँ, प्रतिमान अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (O-SMART)

iii.ध्रुवीय विज्ञान और निम्नतापमंडल अनुसंधान (PACER)

iv.भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान (SAGE)

v.अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और पहुंच (REACHOUT)

प्रमुख बिंदु

i.यह योजना विभिन्न MoES संस्थानों में एकीकृत बहु-विषयक पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान और नवीन कार्यक्रमों के विकास को सक्षम बनाएगी।

ii.R&D प्रयास मौसम और जलवायु, महासागर, निम्नतापमंडल, भूकंपीय विज्ञान और सेवाओं की चुनौतियों का समाधान करेंगे और उनके स्थायी दोहन के लिए जीवित और निर्जीव संसाधनों का पता लगाएंगे।

iii. MoES के समुद्र विज्ञान और तटीय अनुसंधान जहाज योजना के लिए आवश्यक अनुसंधान सहायता प्रदान करते हैं।

R&D संस्थान:

MoES की अनुसंधान & विकास (R&D) और परिचालन (सेवाएँ) गतिविधियाँ MoES के 10 संस्थानों द्वारा की जाती हैं:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
- मध्यम दूरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए ाष्ट्रीय केंद्र (NCMRWF)
- समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र (CMLRE)
- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR)
- राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS)
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT)
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), हैदराबाद
- राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे
- राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (NCESS)

मंत्रिमंडल ने संयुक्त लघु उपग्रह के विकास पर सहयोग के संबंध में ISRO और MRIC के बीच MoU को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त लघु उपग्रह के विकास पर सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और मॉरीशस अनुसंधान और नवाचार परिषद (MRIC) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) का मूल्यांकन किया।

- विदेश मंत्रालय (MEA) के राज्य मंत्री (MoS) V. मुरलीधरन की 'अप्रवासी दिवस' कार्यक्रम के लिए मॉरीशस की यात्रा के दौरान 1 नवंबर 2023 को पोर्ट लुइस, मॉरीशस में MoU पर हस्ताक्षर किए गए थे।

नोट: MRIC मॉरीशस गणराज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और नवाचार मंत्रालय के तत्वावधान में एक कॉर्पोरेट निकाय है।

MoU की विशेषताएं:

i.MoU एक संयुक्त उपग्रह के विकास और MRIC के ग्राउंड स्टेशन के उपयोग पर सहयोग पर ISRO और MRIC के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा की स्थापना को सक्षम करेगा।

ii.यह ISRO और MRIC के बीच छोटे उपग्रहों के संयुक्त कार्यान्वयन को भी सक्षम बनाएगा।

iii.उपग्रह का निर्माण 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 15 महीनों में पूरा किया जाएगा जिसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

iv.मॉरीशस सरकार से निरंतर समर्थन सुनिश्चित करते हुए भविष्य में ISRO के छोटे उपग्रह अभियान के लिए MRIC के ग्राउंड स्टेशन का उपयोग भी MoU में शामिल किया गया है।

पृष्ठभूमि

i.भारत और मॉरीशस के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर देश-स्तरीय समझौते पर पहली बार 1986 में हस्ताक्षर किए गए थे।

- इसके तहत, ISRO ने ISRO के लॉन्च वाहन और उपग्रह अभियानों के लिए ट्रैकिंग और टेलीमेट्री समर्थन के लिए मॉरीशस में एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित किया।

ii.वर्तमान में, भारत और मॉरीशस के बीच अंतरिक्ष सहयोग 29 जुलाई 2009 को हस्ताक्षरित समझौते द्वारा नियंत्रित होता है।

मंत्रिमंडल ने अभियान शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने में भारतीय रेलवे को सहयोग देने के लिए USAID/भारत के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए IR का समर्थन करने के लिए 14 जून 2023 को भारतीय रेलवे (IR), भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास/भारत (USAID/भारत) के बीच हस्ताक्षरित MoU को मंजूरी दे दी।

MoU के बारे में:

i.MoU 5 वर्षों के लिए या दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारी (SAREP) के प्रभावी अंत तक, जो भी कम हो, प्रभावी रहेगा।

ii.इस MoU के तहत सेवाओं के लिए तकनीकी सहायता SAREP पहल के तहत USAID द्वारा प्रदान करने का इरादा है।

iii. MoU में भारतीय रेलवे की ओर से कोई वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल नहीं है।

iv.फोकस क्षेत्र:

- भारतीय रेलवे के लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित दीर्घकालिक ऊर्जा योजना।
- भारतीय रेलवे भवनों के लिए एक ऊर्जा दक्षता नीति और कार्य योजना विकसित करना।
- भारतीय रेलवे के शुद्ध-शून्य दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा खरीद की योजना बनाना।
- विनियामक और कार्यान्वयन बाधाओं को दूर करने के लिए तकनीकी सहायता करना।
- प्रणाली-अनुकूल, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय खरीद के लिए बोली डिजाइन और बोली प्रबंधन समर्थन करना।
- ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने में भारतीय रेलवे का समर्थन करना।
- पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोगात्मक रूप से कार्यक्रमों, सम्मेलनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की मेजबानी करना।

नोट: SAREP USAID भारत का प्रमुख क्षेत्रीय ऊर्जा कार्यक्रम है। यह पांच साल की पहल (2021-26) इन देशों की जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा प्राथमिकताओं के अनुरूप 6 दक्षिण एशियाई देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका) में सस्ती, सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार करती है।

मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दे दी & इसका नाम "महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम" रखा।

PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को **अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा** घोषित करने और इसका नाम "**महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम**" रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

हवाई अड्डे का नाम भारत के महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मिकी को श्रद्धांजलि देता है।

नोट: महर्षि वाल्मिकी की अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ वाल्मिकी संहिता और वशिष्ठ योग संहिता हैं।

मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और गुयाना के बीच MoU पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के पेट्रोलियम & प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) और गुयाना गणराज्य के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित MoU को मंजूरी दे दी। MoU पर 5 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे पंचवर्षीय आधार पर स्वचालित रूप से नवीनीकृत किया जा सकता है।

विशेषताएँ:

i.द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और कच्चे तेल के स्रोत में विविधता लाने और भारत की ऊर्जा & आपूर्ति सुरक्षा में सुधार करने में मदद करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

ii.यह भारतीय कंपनियों को गुयाना के अन्वेषण और उत्पादन (E&P) क्षेत्र में भाग लेने और अपस्ट्रीम परियोजनाओं में वैश्विक तेल & गैस कंपनियों के साथ काम करके अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगा।

iii. MoU में निम्नलिखित शामिल हैं:

गुयाना से कच्चे तेल की सोर्सिंग सहित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य सीरीज

- गुयाना के (E&P) क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की भागीदारी
- कच्चे तेल के शोधन के क्षेत्र में सहयोग
- प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग
- गुयाना में तेल और गैस क्षेत्र में नियामक नीति ढांचे के विकास में सहयोग
- जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र सहित सौर ऊर्जा आदि सहित स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग।

प्रमुख बिंदु:

i.गुयाना दुनिया का सबसे नया तेल उत्पादक बन गया है। 11.2 बिलियन बैरल तेल के बराबर की नई खोजें, कुल वैश्विक तेल & गैस खोजों का 18% और खोजे गए तेल का 32% है।

ii.OPEC (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) वर्ल्ड आयल आउटलुक 2022 के अनुसार, गुयाना की तरल आपूर्ति 2021 में 0.1 mb/d से बढ़कर 2027 में 0.9 mb/d होने की उम्मीद है।

iii.BP स्टैटिस्टिकल रिव्यु ऑफ़ वर्ल्ड एनर्जी 2022 के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी उपभोक्ता, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और बढ़ती एनर्जी जरूरतों के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

<u>मॉरीशस के बारे में:</u>

राजधानी– पोर्ट लुइस

मुद्रा– मॉरीशस रुपया

राष्ट्रपति– पृथ्वीराजसिंह रूपन

<u>गुयाना के बारे में:</u>

राजधानी– जॉर्जटाउन

मुद्रा– गुयाना डॉलर

अध्यक्ष– इरफ़ान अली

18 जनवरी 2024 को मंत्रिमंडल की मंजूरी

18 जनवरी 2024 को, भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है:

i.16वें वित्त आयोग (FC) के लिए पदों का सृजन।

ii.अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र पर कार्य व्यवस्था पर भारत और यूरोपीय आयोग के बीच समझौता ज्ञापन (MoU)

iii.डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने पर भारत और केन्या के बीच MoU।

iv.चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड के बीच आशय ज्ञापन (MoI)।

v.चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इक्वाडोर के बीच MoU।

vi.साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा इक्विटी निवेश।

मंत्रिमंडल ने 16वें FC की सहायता के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के तहत गठित 16वें वित्त आयोग (FC) के लिए संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन पदों यानी संयुक्त सचिव के दो पद और आर्थिक सलाहकार के एक पद के सृजन को मंजूरी दे दी है।

- नए सृजित पदों को आयोग को अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता करने की आवश्यकता है। आयोग में अन्य सभी पद प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप पहले ही सृजित किये जा चुके हैं।
- 16वें FC को केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण की समीक्षा करने, राजस्व बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने और 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा प्रबंधन गतिविधियों के वित्तपोषण का आकलन करने का काम सौंपा गया है।

16वें FC के बारे में:

16वें FC के अध्यक्ष- पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित **डॉ. अरविंद पनगढ़िया**, NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के पूर्व & पहले उपाध्यक्ष, और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और जगदीश भगवती भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

सचिव– ऋत्विक रंजनम पांडे

नोट: 16वां FC 31 अक्टूबर 2025 तक भारत के राष्ट्रपति (वर्तमान में- द्रौपदी मुर्मू) को पांच वर्षों (1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है।

अतिरिक्त जानकारी:

i.15वें FC का गठन 6 साल (2020-21 से 2025-26) के लिए सिफारिशें करने के लिए 27 नवंबर 2017 को किया गया था।

ii.FC के अध्यक्ष राजनेता, अर्थशास्त्री और पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी **नंद किशोर सिंह** थे।

iii.प्रथम FC का गठन 1952 में क्षितिज चंद्र (KC) नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था।

मंत्रिमंडल ने भारत और यूरोपीय आयोग के बीच MoU को मंजूरी दी:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 नवंबर 2023 को **यूरोपीय संघ (EU)-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद** (TTC) के ढांचे के तहत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार पर कार्य व्यवस्था पर **भारत सरकार (GoI)** और यूरोपीय आयोग के बीच हस्ताक्षरित एक MoU को मंजूरी दे दी।।

- यह MoU सरकार-से-सरकार (G2G) और व्यापार-से-व्यापार(B2B) सहयोग के माध्यम से अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को बढ़ाएगा, अर्धचालक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की ताकत का लाभ उठाएगा।

पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें भारत, EU ने अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग को गहरा करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

उद्देश्य: उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए अर्धचालकों को बढ़ाने की दिशा में भारत और EU के बीच सहयोग को मजबूत करना

पृष्ठभूमि:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**) सक्रिय रूप से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देता है, और विभिन्न अर्धचालक सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अर्धचालक और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया है।

- डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के तहत भारत अर्धचालक मिशन (ISM) अर्धचालक विकास को भी संचालित करता है और भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करता है।
- MeitY को द्विपक्षीय सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए विभिन्न देशों के साथ MoU पर हस्ताक्षर करके द्विपक्षीय और क्षेत्रीय ढांचे के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है।

मंत्रिमंडल ने भारत और केन्या के बीच MoU को मंजूरी दी:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए MeitY, GoI और सूचना, संचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय, केन्या गणराज्य के बीच 5 दिसंबर 2023 को हस्ताक्षरित MoU को मंजूरी दे दी।

- यह MoU पार्टियों के हस्ताक्षर की तारीख यानी 5 दिसंबर, 2023 को लागू हुआ और **3 साल** तक लागू रहेगा।

प्रमुख बिंदु:

i.इस MoU के माध्यम से, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के क्षेत्र में G2G और B2G दोनों द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाएगा।

ii.इसमें IT के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सहयोग की भी परिकल्पना की गई है।

iii.यह MoU सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा, और भारत और केन्या के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के अंतिम लक्ष्य के साथ डिजिटल क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा।

मंत्रिमंडल ने भारत और नीदरलैंड के बीच MoI को मंजूरी दी:

मंत्रिमंडल ने 7 नवंबर, 2023 को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन **(CDSCO)**, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय **(MoH&FW)**, GoI और **स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय, नीदरलैंड** के बीच औषधि मूल्यांकन बोर्ड, स्वास्थ्य और युवा देखभाल निरीक्षणालय, मानव विषयों से जुड़े अनुसंधान पर केंद्रीय समिति की ओर से हस्ताक्षरित एक आशय ज्ञापन **(MoI)** को भी मंजूरी दी।

- इस MoU में चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई है।

प्रमुख बिंदु:

i.CDSCO और **स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय** के बीच औषधि मूल्यांकन बोर्ड, स्वास्थ्य और युवा देखभाल निरीक्षणालय, अनुसंधान पर केंद्रीय समिति की ओर से चिकित्सा उत्पादों के विनियमन से संबंधित मामलों में मानव विषयों को उनकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा की स्थापना की जाएगी।

ii.यह MoI फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए कच्चे माल, जैविक उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों सहित फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित चिकित्सा उत्पादों के विनियमन की बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करेगा।

iii.यह भारत के लिए विदेशी मुद्रा आय के लिए चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा।

मंत्रिमंडल ने भारत और इक्वाडोर के बीच MoU को मंजूरी दी:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर CDSCO और Agencia Nacional de Regulaction, Control Y Vigilancia Sanitria - ARCSA, डॉक्टर लियोपोल्डो इज़क्विएटा पेरेज़, इक्वाडोर गणराज्य के बीच 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित MoU से भी अवगत कराया।

प्रमुख बिंदु:

i.यह MoU चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य नियामक पहलुओं की समझ को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

ii.यह भारत से दवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद करता है जिसके परिणामस्वरूप फार्मास्युटिकल क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं।

iii.यह चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा जिससे विदेशी मुद्रा आय होगी।

मंत्रिमंडल ने SECL, MCL और CIL द्वारा इक्विटी निवेश को मंजूरी दी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी।

नोट: SECL और MCL दोनों CIL की सहायक कंपनियां हैं।

विवरण:

SECL:

CCEA ने SECL और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) के संयुक्त उद्यम (JV) के माध्यम से मध्य प्रदेश (MPPGCL) के ग्राम चचाई में अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन में 1 x 660 मेगावाट (MW) सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट (TPP) स्थापित करने के लिए SECL द्वारा इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- CCEA ने प्रस्तावित पावर प्लांट के लिए 5,600 करोड़ रुपये (±20% की सटीकता) के अनुमानित प्रोजेक्ट कैपेक्स के साथ 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात और JV कंपनी में 49% इक्विटी निवेश पर विचार करते हुए SECL द्वारा 823 करोड़ रुपये (± 20%) की इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है।

MCL:

CCEA ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में MCL की सहायक कंपनी महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (MBPL) के माध्यम से 2 x 800 MW TPP स्थापित करने के लिए MCL द्वारा इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- CCEA ने MBPL के माध्यम से 15,947 करोड़ रुपये (±20%) के अनुमानित प्रोजेक्ट कैपेक्स के साथ प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए 4,784 करोड़ रुपये (±20%) की इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है।

CIL:

CCEA ने CIL द्वारा SECL-MPPGCL के संयुक्त उद्यम (823 करोड़ रुपये ± 20%) और MBPL (4,784 करोड़ रुपये ± 20%) में अपने शुद्ध मूल्य के 30% से अधिक इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दे दी।

- CIL अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से इन दो पिथेड TPP की स्थापना करेगी।

हाल के संबंधित समाचार:

i.प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों: लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REE) के लिए रॉयल्टी दरों को निर्दिष्ट करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी।

ii.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "मेरा युवा भारत" (MY भारत) नामक एक स्वायत्त संगठन के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी। तेजी से संचार, सोशल मीडिया, डिजिटल अवसरों और उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते परिदृश्य के जवाब में, सरकार 'मेरा युवा भारत' (MY भारत) नामक एक स्वायत्त इकाई बना रही है, जो युवाओं को जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' द्वारा निर्देशित है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के बारे में:

यह भारत में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है।

भारत के औषधि महानियंत्रक– डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली

PARLIAMENT

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिसंबर 2023 को दो विधेयकों को मंजूरी दे दी

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 सहित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी।

- भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर एक विधेयक एक अधिनियम में बदल जाता है और औपचारिक रूप से आधिकारिक राजपत्र में इसकी घोषणा की जाती है। परिणामस्वरूप, उपरोक्त विधेयक अब अधिनियम के रूप में अधिनियमित हो गए हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023

विधेयक का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति के लिए एक तंत्र स्थापित करना है।

- यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 की जगह लेती है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

इस कानून का उद्देश्य CEC और अन्य EC की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

- नए कानून में नियुक्ति, वेतन और CEC और अन्य EC को हटाने जैसे पहलू शामिल हैं।

i.नियुक्ति: राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर CEC और EC की नियुक्ति करेंगे, जिसमें प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।

- CEC और अन्य EC उस तारीख से **6 वर्ष** की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है या जब तक वह **पैंसठ वर्ष** की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो।
- इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी।
- इससे पहले चयन समिति में 3 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।
- आदेश से पहले केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाती थीं

नोट- राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक ने **भारत के मुख्य न्यायाधीश** को चयन समिति से हटा दिया है।

ii.खोज समिति: विधेयक में CEC और EC के पदों पर विचार के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए एक खोज समिति की स्थापना के संबंध में भी प्रावधान हैं।

- खोज समिति की अध्यक्षता **कानून और न्याय मंत्री** करेंगे और इसमें सचिव के पद से नीचे के दो सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा।

iii.वेतन: CEC और EC का वेतन और सेवा शर्तें **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश** के बराबर होंगी।

iv.इस्तीफा और निष्कासन: विधेयक संविधान में निर्दिष्ट CEC और EC को हटाने के तरीके को बरकरार रखता है।

- CEC को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। EC को केवल CEC की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मार्च 2023 में फैसला सुनाया था कि CEC और EC की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जब तक कि उनकी नियुक्तियों पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निर्धारित कोई संसदीय कानून लागू नहीं किया गया था।

प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023

प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की जगह लेती है।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधित मंत्रालय है जो विधेयक पर प्रकाश डालता है।

i.इस विधेयक का उद्देश्य पंजीकरण और घोषणा प्रक्रिया को आधुनिक और सरल बनाना है। इससे प्रकाशकों को प्रक्रियाओं को आसान बनाने और घोषणाओं और भरने की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।

- समय-समय पर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किसी पत्रिका के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन एक साथ करना होगा।
- निर्दिष्ट प्राधिकारियों को 60 दिनों के भीतर फीडबैक प्रदान करना आवश्यक है।
- विधेयक पंजीकरण प्रमाणपत्र और स्वामित्व आवंटन प्रदान करने में जिला मजिस्ट्रेट/स्थानीय प्राधिकारी की न्यूनतम भूमिका का प्रावधान करता है।

ii.यह विधेयक आतंकवाद के दोषी व्यक्तियों या राज्य सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर प्रकाशित करने से रोकता है।

iii.1867 के अधिनियम से तुलना

- विधेयक कुछ उल्लंघनों के लिए कारावास को जुर्माने से बदल देता है
- भारतीय प्रेस परिषद के नेतृत्व में एक अपीलीय तंत्र शुरू किया गया है।
- प्रशासनिक शक्ति जिला मजिस्ट्रेट से नव स्थापित प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को स्थानांतरित कर दी गई है।

<u>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बारे में</u>

केंद्रीय मंत्री: अनुराग सिंह ठाकुर (लोकसभा-हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

राज्य मंत्री: डॉ. L. मुरुगन (राज्यसभा - मध्य प्रदेश)

सरकार ने CCS (पेंशन) नियम 2021 में संशोधन किया; महिला सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बच्चे को नामांकित करने की अनुमति देता है

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने **केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) (पेंशन) नियम, 2021** में **संशोधन** किया है, ताकि महिला सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को अपने पति की वरीयता में पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बच्चे/बच्चों को नामांकित करने की अनुमति मिल सके।

नोट: CCS(पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के उप-नियम (8) और (9) में कहा गया है कि यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के पति या पत्नी बच जाते हैं, तो शुरू में पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है, परिवार के अन्य सदस्य केवल तभी पात्र होते हैं जब पति या पत्नी अयोग्य हो जाते हैं या उनका निधन हो जाता है।

संशोधन का विवरण:

i.किसी भी वैवाहिक कलह के कारण अदालत में **तलाक की कार्यवाही दायर करने** या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत **मामला दर्ज करने** के लिए महिला सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी इस आशय का अनुरोध कर सकता है कि उसकी मृत्यु की स्थिति में, उसके पति की प्राथमिकता में उसके पात्र बच्चे को पारिवारिक पेंशन दी जाए।

ii.उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार वितरित की जाएगी,

(a) पात्र बच्चों के बिना विधुर - विधुर को पारिवारिक पेंशन देय है।

(b) नाबालिग बच्चों वाला विधुर या मानसिक विकार या विकलांगता वाले बच्चे

- पारिवारिक पेंशन विधुर (अभिभावक के रूप में कार्य करने वाले) को जाती है।
- यदि विधुर अभिभावक नहीं रह जाता है, तो पेंशन वास्तविक अभिभावक के माध्यम से बच्चे को भेज दी जाती है।
- वयस्क होने पर, बच्चे को पात्र होने तक पेंशन मिलती है।

(c) विधुर जिनके बच्चे वयस्क हो गए हैं लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं – पारिवारिक पेंशन बच्चे/बच्चों को देय है।

नोट:

यदि कोई बच्चा/बच्चों CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत पात्र नहीं रह जाता है, तो पारिवारिक पेंशन अन्य पात्र बच्चे/बच्चों को दे दी जाती है।

आख़िरकार, नियम 50 के तहत बच्चे अयोग्य हैं, विधुर को मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन मिलती है।

LAUNCHES & INAUGURATION

MoT & MoEF&CC ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चिल्का झील में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

पर्यटन मंत्रालय (**MoT**) ने पर्यावरण, वन & जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (**MoEF&CC**) के सहयोग से 6 जनवरी 2024 को ओडिशा के रामसर स्थल **चिल्का झील** में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत पांचवां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के बारे में:

i.MoEF&CC ने इन स्थलों पर प्रकृति पर्यटन को मजबूत करने और स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए विभिन्न रामसर स्थलों के आसपास स्थानीय समुदाय के सदस्यों के विकास के लिए अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना शुरू की।

- क्षमता निर्माण अमृत धरोहर योजना का मुख्य हिस्सा है जो रामसर स्थलों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देता है।

ii.क्षमता निर्माण योजना के पहले चरण में, पांच प्राथमिकता वाले रामसर स्थलों, अर्थात् सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (हरियाणा), सिरपुर आर्द्रभूमि (मध्य प्रदेश), यशवंत सागर (मध्य प्रदेश), भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (ओडिशा), और चिल्का झील (ओडिशा) की पहचान की गई।

- पाँच स्थलों में से, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसंबर 2023 में पूरा हो गया। चौथा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में 5 जनवरी, 2024 को पूरा हुआ।

iii.अमृत धरोहर का कार्यान्वयन 5 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर शुरू हुआ और **5 जून, 2026** तक जारी रहेगा।

चिल्का झील में प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में:

i.इस पहल के तहत, 15-15 दिनों के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम (**ALP**), और पर्यटन नाविक प्रमाणपत्र (**PNC**) आयोजित किए जाएंगे।

ii.चिलिका विकास प्राधिकरण (CDA) की मदद से कार्यक्रम के लिए कुल 60 प्रतिभागियों (प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 30) की पहचान की गई और उन्हें **प्रकृति-मार्गदर्शक** के रूप में प्रमाणित किया गया।

नोट:

i.ओडिशा में चिल्का झील और **राजस्थान** में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी।
ii.चिलिका झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।

रामसर ब्यूरो के बारे में:

महासचिव - मुसोंडा मुंबा
मुख्यालय - ग्लैंड, स्विट्जरलैंड
i.रामसर स्थलों आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन (1971) के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है।
ii.जनवरी 2024 तक, भारत में 75 रामसर स्थलों हैं।
रामसर स्थलों की पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें

डन & ब्रैडस्ट्रीट और ज्यूपिटर वैगन्स ने भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधि सूचकांक का अनावरण किया

फ्लोरिडा (संयुक्त राज्य अमेरिका) स्थित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (D&B) ने **ज्यूपिटर वैगन्स लिमिटेड** के सहयोग से 12 से 14 अक्टूबर 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिल्ली में में 15वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी (IREE 2023) के दौरान **भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधि (IRFA)** सूचकांक का अनावरण किया।

- यह एक त्रैमासिक रिपोर्ट है जो भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधि की गतिशीलता का व्यापक और डेटा-संचालित मूल्यांकन प्रदान करती है।
- IRFA सूचकांक भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधि की जटिलताओं की निगरानी और समझने के लिए अपनी तरह का पहला उपकरण बन गया है।

नोट: D&B लगभग 200 वर्षों से व्यवसाय निर्णय डेटा और विश्लेषण का अग्रणी वैश्विक प्रदाता है।

रेलवे माल ढुलाई गतिविधि आशावाद सूचकांक (RFAOI):

i.यह एक अनूठा सूचकांक है जिसका लक्ष्य अपेक्षित रेल माल ढुलाई गतिविधि पर रेलवे के उपयोगकर्ताओं (उद्योग के खिलाड़ियों और रसद सेवा प्रदाताओं) के आशावाद स्तर को पकड़ना है।
ii.डन & ब्रैडस्ट्रीट और ज्यूपिटर वैगन्स भारत में अपनी तरह का पहला, त्रैमासिक RFAOI, भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधि (IRFA) सूचकांक पेश कर रहे हैं।

IRFA सूचकांक और इसका मूल्यांकन:

i.यह अग्रणी सूचकांक रेलवे माल ढुलाई मॉडल शेयर को बढ़ावा देने और रेलवे माल आपूर्ति श्रृंखला के भीतर विभिन्न हितधारकों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ii.यह अपने माल के परिवहन के लिए रेलवे का उपयोग करने के प्रति भारत भर में व्यवसायों के आशावाद के स्तर को पकड़ने के लिए सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।
iii.IRFA सूचकांक रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के डेटा और उपयोगकर्ता सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि को समाहित करता है।

दो उप-सूचकांक:

त्रैमासिक रिपोर्ट में 2 महत्वपूर्ण उप-सूचकांक शामिल हैं:
गतिविधि उप-सूचकांक: रेल मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर, यह उप-सूचकांक रेलवे माल ढुलाई गतिविधि के मात्रात्मक पहलू को दर्शाता है।
अनुभव उप-सूचकांक: रेलवे माल उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण से प्राप्त, यह उप-सूचकांक गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है और आगामी तिमाही के लिए उपयोगकर्ता आशावाद स्तर को मापता है।

सूचकांक मूल्य और व्याख्या:

i.सूचकांक मान 0 से 100 तक होता है।

ii.50 का मान साल-दर-साल (YoY) आधार पर रेलवे माल ढुलाई गतिविधि के तटस्थ स्तर को दर्शाता है।

IRFA सूचकांक के लाभ:

i.यह नीति निर्माताओं को रेलवे माल ढुलाई गतिविधि की बारीकी से निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

ii.यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों से निपटने में सहायता करते हुए अच्छी तरह से सूचित रहें।

मुख्य निष्कर्ष:

i.2023 की Q3 के लिए IRFA सूचकांक 48 पर है, जो 2022 की इसी तिमाही की तुलना में रेल माल ढुलाई गतिविधि के उप-तटस्थ स्तर का संकेत देता है।

ii.56 पर अनुभव सूचकांक की तुलना में आशावाद सूचकांक 60 पर है, जो वर्तमान तिमाही (Q3 2023) के लिए रेलवे माल ढुलाई गतिविधि को इंगित करता है, जो आगामी तिमाही (Q4 2023) के लिए बढ़ी हुई आशावाद का सुझाव देता है।

iii.उपयोगकर्ता कंटेनरों (68 पर आशावाद सूचकांक) और कार्गो हैंडलिंग मशीनरी (61 पर आशावाद सूचकांक) की उच्च मांग की उम्मीद करते हैं।

iv.केवल 16% उत्तरदाता अपनी 50% से अधिक माल ढुलाई रेलवे के माध्यम से करते हैं; 53% ने सड़क मार्ग और 50% से अधिक ने परिवहन का विकल्प चुना।

v.मध्य और उत्तरी रेलवे के उपयोगकर्ता अन्य 3 क्षेत्रों की तुलना में 2024 की चौथी तिमाही के लिए सबसे अधिक आशावाद व्यक्त करते हैं।

vi.पूंजीगत सामान क्षेत्र रेल माल ढुलाई गतिविधि में वृद्धि के लिए सबसे अधिक आशावादी बनकर उभरा है, जो 14 क्षेत्रों में सबसे अधिक है, जो निवेश गतिविधि में वृद्धि का संकेत देता है।

vii.75% उत्तरदाताओं ने रेलवे माल परिचालन को कुशल बताया।

viii.लागत-प्रभावशीलता गति और विश्वसनीयता से अधिक है, जो रेलवे माल ढुलाई के लिए प्राथमिक मांग चालक के रूप में उभर रही है।

ix.कनेक्टिविटी कोई बाधा नहीं है, लेकिन नेटवर्क की भीड़ और माल की क्षति/हानि रेलवे माल परिवहन में चुनौतियां पैदा करती है।

नोट:

- पिछले वर्ष की तुलना में Q4 2023 के लिए आशावाद में वृद्धि से रेल माल ढुलाई गतिविधि में वृद्धि और उपयोगकर्ता अनुभवों में सुधार का संकेत मिलता है।
- लगभग 50% उत्तरदाता अपनी परिवहन रणनीति में रेलवे को महत्वपूर्ण मानते हैं।
- केवल 16% अपने अधिकांश माल का परिवहन रेलवे के माध्यम से करते हैं, जो अधूरी मांग और विकास की संभावना का संकेत देता है।

<u>हालि के संबंधित समाचार:</u>

वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) को रेल मंत्रालय के तहत 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) अर्थात् इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON) और RITES लिमिटेड (RITES) को नवरत्न का दर्जा दिया गया है।

<u>जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के बारे में:</u>

प्रबंध निदेशक (MD)- श्री विवेक लोहिया

मुख्यालय– कोलकाता, पश्चिम बंगाल

सम्मिलित–2006

डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (D&B) भारत के बारे में:

प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)- अविनाश गुप्ता

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

परिचालन की शूरुआत– 1995

NITI आयोग, MoA&FW & FAO ने संयुक्त रूप में इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीफूड सिस्टम्स इन इंडिया लॉन्च किया

NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय **(MoA&FW)**, और संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन **(FAO)** ने संयुक्त रूप से **'इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीफूड सिस्टम्स इन इंडिया'** लॉन्च किया।

- फोरम को 18-19 जनवरी, 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित बहु-हितधारक बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य:

संयुक्त पहल का उद्देश्य भारत में सरकार, निजी क्षेत्रों, किसान संगठनों और वित्तीय संस्थानों के बीच एडवांसिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीफूड सिस्टम्स को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु:

i.इन्वेस्टमेंट में इक्विटी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थानों (DFI) द्वारा समर्थित अनुदान, ग्रीन और सोशल बॉन्ड्स, और निगमों, मिश्रित वित्त और उद्यम पूंजी फर्मों के माध्यम से अन्य गारंटी या आउटपुट-आधारित वित्तपोषण शामिल हैं।

ii.फोरम के दौरान **छह मुख्य क्षेत्रों**, अर्थात क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलूशन्स, फाइनेंसिंग फॉर एग्रीफूड सिस्टम्स, क्लाइमेट रेसिलिएंट वैल्यू चेन्स, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेज फॉर क्लाइमेट रेसिलिएंस, और जेंडर मैनस्ट्रीमिंग एंड सोशल इन्क्लूसिव फॉर क्लाइमेट रेसिलिएंस पर चर्चा की गई।

प्रमुख लोगों:

i.इस कार्यक्रम में प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य, NITI आयोग; मनोज आहूजा, सचिव, MoA&FW; शोम्बी शार्प, भारत में UN के स्थानीय समन्वयक; ताकायुकी हागिवारा, भारत में FAO प्रतिनिधि ने भाग लिया।

प्रतिभागी:

बैठक में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट **(NABARD)**, इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च **(ICAR)**, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द सेमि-एरिड ट्रॉपिक्स **(ICRISAT)**, विश्व बैंक और UN एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के बारे में:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) – B.V.R. सुब्रमण्यम

मुख्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली

स्थापना – 2015

PM मोदी ने अयोध्या राम मंदिर पर स्मारक डाक टिकट & पुस्तक जारी की

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित **छह** विशेष स्मारक **डाक टिकट** जारी किए हैं और भगवान राम को चित्रित करने वाले विभिन्न देशों द्वारा जारी किए गए टिकटों वाली एक पुस्तक भी जारी की है।

स्मारक डाक टिकटों के बारे में:

i.स्मारक संग्रह में छह विशिष्ट टिकटें शामिल हैं, जिनमें राम जन्मभूमि मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के चित्रण शामिल हैं।
ii.राम जन्मभूमि मंदिर पर लघु शीट भी जारी की गई, जिसमें छह डाक टिकट और भगवान राम से जुड़े अन्य डिजाइन हैं।
iii.टिकटों के अन्य डिजाइनों में राम जन्मभूमि मंदिर, प्रतिष्ठित चौपाई 'मंगल भवन अमंगल हारी' (तुलसीदास के महाकाव्य 'रामचरितमानस' की पंक्तियाँ), सूर्य (सुनहरी पत्तियों का उपयोग करके किरणों को चित्रित किया गया था), 'सूर्यवंशी' राम का प्रतीक, पवित्र सरयू नदी, और मंदिर में और उसके आसपास की मूर्तियां शामिल हैं।

टिकट पुस्तक के बारे में:

i.48 पृष्ठों की इस पुस्तक में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ और बारबुडा, कंबोडिया, कनाडा, चेक गणराज्य, फिजी, जिब्राल्टर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गुयाना, ग्रेनेडा, सिंगापुर, लाओ PDR, नेपाल, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन, और टोगो, और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए टिकटों को शामिल किया गया है।
ii.टिकट पुस्तक का उद्देश्य दुनिया भर के विभिन्न समाजों पर भगवान राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील और प्रभाव को प्रदर्शित करना है।

नोट:

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का अभिषेक समारोह (प्राण प्रतिष्ठा) 22 जनवरी 2024 को होना है।

MoPNG हरदीप सिंह पुरी ने अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने के लिए पहला पायलट परियोजना लॉन्च किया

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (MoPNG) मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने पुणे, महाराष्ट्र में **प्राज इंडस्ट्रीज** लिमिटेड अनुसंधान और विकास (R&D) इकाई में अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने के लिए पहली पायलट अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी परियोजना का उद्घाटन किया है।

- यह परियोजना टिकाऊ जैविक विमानन ईंधन **(SAF)** का उत्पादन करेगी।
- इस परियोजना का शुभारंभ प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद चौधरी की उपस्थिति में किया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO से जुड़े CPL के लिए समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

13 जनवरी, 2024 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय **(MoD)** ने सीमा सड़क संगठन **(BRO)**/जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स**(GREF)** उनकी चल रही परियोजनाओं के लिए लगे आकस्मिक भुगतान वाले मजदूरों **(CPL)** के लिये **समूह (टर्म) बीमा योजना** शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह योजना मृत्यु के मामले में CPL के परिवारों/निकट संबंधियों को बीमा के रूप में **10 लाख रुपये** प्रदान करती है।

इसके पीछे कारण:

i.खतरनाक कार्य वातावरण में CPL द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों का समाधान करना है।
ii.रिपोर्ट की गई मौतों पर विचार करते हुए मनोबल बढ़ाना है।

प्रमुख बिंदु:

i.बीमा योजना भारत के एकांत और दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्यरत CPL के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय के रूप में कार्य करती है।
ii.यह अप्रत्याशित परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, CPL के परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

CPL की बेहतरी के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम:

i.नश्वर अवशेषों का संरक्षण, परिचारकों के लिए परिवहन भत्ता।
ii.अंतिम संस्कार सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई।

iii.मृत्यु की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए 50,000 रुपये का अग्रिम भुगतान।

रक्षा मंत्रालय (MoD) के बारे में:

केंद्रीय मंत्री–राजनाथ सिंह (निर्वाचन क्षेत्र-लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

राज्य मंत्री (MoS)– अजय भट्ट (निर्वाचन क्षेत्र-नैनीताल-उधमसिंह नगर, उत्तराखंड)

MoE ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नए नियम जारी किए; 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन नहीं होगा

19 जनवरी, 2023 को शिक्षा मंत्रालय (MoE) के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने **'गाइडलाइन्स फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024'** जारी किए हैं, जो कोचिंग सेंटर्स को 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के नामांकन पर रोक लगाता है।

- छात्रों की बढ़ती आत्महत्याओं, अध्ययन केंद्रों पर अत्यधिक ऊंची फीस और मानसिक दबाव के बीच यह फैसला लिया गया है।

उद्देश्य:

i.भारत में कोचिंग सेंटर्स के लिए रेगुलेटरी उपाय प्रदान करना

ii.कोचिंग सेंटर्स में नामांकित छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें आवश्यक सुरक्षा, मार्गदर्शन और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना।

कोचिंग सेंटर्स के पंजीकरण के लिए मुख्य नियम:

i.ट्यूटर्स के पास स्नातक की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

ii.माता-पिता/छात्रों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी देने से मना किया गया है।

iii.16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं किया जा सकता; माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही नामांकन की अनुमति है।

iv.कोचिंग सेंटर को ट्यूटर योग्यता, पाठ्यक्रम, अवधि, छात्रावास सुविधाओं, फीस, आसान निकास और धनवापसी नीतियों और छात्र सफलता के आंकड़ों के विवरण के साथ एक अद्यतन वेबसाइट बनाए रखनी चाहिए।

v.नियमित स्कूल समय के दौरान कक्षाएं संचालित करने पर प्रतिबंध होगा।

vi.यदि छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और निर्धारित अवधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ रहा है, तो छात्रावास शुल्क और मेस शुल्क आदि के साथ शेष अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर 10 दिनों के भीतर रिफंड किया जाना चाहिए।

vii.साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई मूल्यांकन-परीक्षा/परीक्षा नहीं होगी।

viii.क्षेत्रीय त्योहारों के दौरान, कोचिंग सेंटर पारिवारिक जुड़ाव और भावनात्मक समर्थन के लिए छुट्टी देता है।

ix.उचित समय के साथ प्रतिदिन 5 घंटे तक सीमित कक्षाएं।

x.इंजीनियरिंग और मेडिकल विकल्पों के अलावा, छात्रों ने भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वैकल्पिक करियर विकल्पों पर जानकारी प्रदान की।

केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने केरल में कृत्रिम भित्तियों के लिए परियोजना लांच की

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (**MoFAHD**) के केंद्रीय मंत्री **परषोत्तम रूपाला** ने केरल के तिरुवनंतपुरम के विझिंजम में समुद्र तल में कृत्रिम भित्तियाँ जमा करने की परियोजना को विर्चुअलि लांच किया।

- इस परियोजना का उद्देश्य केरल के जल में मछली की आबादी को बढ़ाकर मछुआरों की आय में वृद्धि करना है।

परियोजना के बारे में:

i.यह परियोजना भारत सरकार **(GoI)** और केरल सरकार की एक संयुक्त पहल है।

ii.यह परियोजना केरल राज्य तटीय क्षेत्र विकास निगम **(KSCADC)** द्वारा MoFAHD की प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना **(PMMSY)** के तहत कार्यान्वित की गई है।

iii.भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद **(ICAR)** - केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान **(CMFRI)** परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
iv.यह परियोजना 13.02 करोड़ रुपये के बजट के साथ: 60% (7.812 करोड़ रुपये) भारत सरकार द्वारा और 40% (5.208 करोड़ रुपये) केरल सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई है।

प्रमुख बिंदु:

i.परियोजना के चरण 1 के तहत, तिरुवनंतपुरम जिले के पोझियूर से वर्कला तक 42 मछली पकड़ने वाले गांवों (प्रत्येक गांव में 150 भित्तियाँ) में 6,300 कृत्रिम भित्तियाँ बिछाई जाएंगी।
ii.इस परियोजना के तहत, प्रत्येक 42 गांवों के लिए 3 अलग-अलग आकारों में रीइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (RCC) भित्तियाँ भित्तियाँ- ट्राईएंगुलर (80 इकाइयां), फ्लोरल (35 इकाइयां), और फ़्यूज्ड पाइप टाइप (35 इकाइयां) आवंटित की गईं।
iii.ये मॉड्यूल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम **(GPS)** की मदद से समुद्र तल पर 12 से 15 थाह की गहराई पर स्थापित किए जाएंगे।
iv.ये भित्तियाँ एक कृत्रिम आवास बनाती हैं जिससे मछली प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं।
नोट: एक थाह 6 फीट (1.8288 मीटर) के बराबर होता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है।

अतिरिक्त जानकारी:

i.PMMSY के तहत, GoI ने केरल में कृत्रिम भित्तियाँ स्थापना और सतत मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 302 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
ii. MoFAHD के तहत मत्स्य पालन विभाग ने भारत के समुद्र तट के साथ 3,477 मछली पकड़ने वाले गांवों में कृत्रिम भित्तियों के कार्यान्वयन का सुझाव दिया है।

PM मोदी ने UP के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया

22 जनवरी 2024 को, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश (UP) के अयोध्या में नव निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर (मंदिर) में **श्री रामलला** की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा / प्राण शक्ति की स्थापना) समारोह में भाग लिया।

- समारोह की रस्मों का नेतृत्व PM ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के साथ किया।
- अभिषेक समारोह का संचालन वाराणसी, UP के पुजारी **लक्ष्मीकांत दीक्षित** के नेतृत्व में पुजारियों की एक टीम ने किया।

रामलला की मूर्ति के बारे में:

मंदिर के गर्भगृह में रखी गई 51 इंच (4.25 फीट) की रामलला मूर्ति को मैसूर (कर्नाटक) स्थित अरुण योगीराज ने गढ़ा था।

विशेषताएँ:

i.मूर्ति में भगवान राम को पांच साल की उम्र यानी राम लला के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि इस उम्र को मासूमियत का युग माना जाता है।
ii.काले पत्थर से बनी मूर्ति मासूमियत, दिव्यता और राजसी गौरव को प्रदर्शित करती है। काला पत्थर मूर्ति की दीर्घायु सुनिश्चित करता है।
iii.राम लल्ला की मूर्ति के मुड़े हुए हाथों को घुटनों तक पहुंचने के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है, जो भगवान राम की 'अजानुबाहु' (एक व्यक्ति जिसकी बाहों की लंबाई ऐसी है कि उसकी उंगलियां उसके घुटने को छूती हैं) की विशेषता को दर्शाती हैं।
iv.मूर्ति के हाथ में एक सुनहरा धनुष और तीर है।

v.राम लला की मूर्ति को तैयार करने के लिए 'कृष्ण शिला पत्थर' का उपयोग किया गया था। इस्तेमाल किया गया पत्थर 2.5 अरब साल पुराना था और ये पत्थर कर्नाटक के मैसूर जिले में पाए जाते हैं।
vi.अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की नई मूर्ति का नाम 'बालक राम' रखा गया है।

डिज़ाइन विवरण:

i.मूर्ति भगवान विष्णु के सभी दस अवतारों: मत्स्य (मछली), कूर्म (कछुआ), वराह (सूअर), नरसिम्हा (मानव-शेर), वामन (बौना), परशुराम (योद्धा), राम (राजकुमार), कृष्ण (चरवाहा), बुद्ध (प्रबुद्ध), और कल्कि (भविष्य का अवतार) को प्रदर्शित करती है।
ii.भगवान हनुमान को मूर्ति के दाहिने पैर के पास और भगवान गरुड़ (भगवान विष्णु की सवारी) को बाएं पैर के पास उकेरा गया है।
iii.धार्मिक प्रतीक: मूर्ति में स्वस्तिक और ओम, चक्र, गदा और शंख के साथ उत्कीर्ण किया गया था।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में:

i.डिजाइन & निर्माण:

राम जन्मभूमि मंदिर को प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत B सोमपुरा, 81, और उनके बेटे आशीष, 51 ने **नागर शैली की मारू-गुर्जर वास्तुकला** में डिजाइन किया था, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है।

- इसका निर्माण **लार्सन एंड टुब्रो** (L&T) द्वारा किया गया है।
- वहीं, **राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र** राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख करता है।

ii.लागत: मंदिर का निर्माण **1800 करोड़ रुपये** की अनुमानित लागत पर किया गया था।
iii.आकार: तीन मंजिला मंदिर, परिसर **70 एकड़** में फैला है, जिसमें से मंदिर और परिसर 5.5 एकड़ में फैला है। मंदिर की लंबाई (पूर्व-पश्चिम) 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मुख्य मंदिर क्षेत्र **2.67 एकड़** में फैला है।

प्रमुख बिंदु:

i.यह **गुलाबी बलुआ पत्थर** से बना है और **काले ग्रेनाइट** से बना है।
ii.मंदिर विशेष रूप से स्टील या लोहे से परहेज करता है, प्राचीन निर्माण प्रथाओं का पालन करने और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए पारंपरिक निर्माण सामग्री का चयन करता है।
iii.कुल 392 स्तंभों और 44 दरवाजों द्वारा समर्थित, मंदिर तीन मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है।
iv.स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं, भगवानों और देवियों के जटिल चित्रण प्रदर्शित हैं।
v.राम मंदिर के अलावा सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान, भगवान शिव, माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, और हनुमान जी का मंदिर के कुल **6 मंदिर** होंगे।

अन्य मुख्य बातें:

i.PM मोदी ने अयोध्या राम मंदिर परिसर में "जटायु" की एक मूर्ति का भी अनावरण किया।
ii.अभी तक मंदिर का केवल चरण- । पूरा हुआ है यानी भूतल खोला गया है, और बाकी 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
iii.निर्माण कार्य शहर के पुनरुद्धार का हिस्सा है, जिसकी अनुमानित लागत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
iv.इस कार्यक्रम में जीवन के सभी क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों और भारत के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.राम मंदिर का निर्माण 2019 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद शीर्षक मुकदमे पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) के फैसले के बाद हुआ।

ii.श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को किया गया था।
iii.PM मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी।

समारोह के लिए दो क्यूब-BHISHM मोबाइल अस्पताल तैनात किए गए

आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन परियोजना के तहत **दो क्यूब-BHISHM मोबाइल** अस्पतालों को 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के लिए चिकित्सा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिए अयोध्या में तैनात किया गया था।
i.यह क्यूब **'प्रोजेक्ट BHISHM-भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री'** का हिस्सा है।
ii.क्यूब को त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर ध्यान देने के साथ 200 हताहतों के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है।
iii.यह AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डेटा एनालिटिक्स सहित नवीन उपकरणों से लैस है, एड क्यूब आपात स्थिति के दौरान प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और चिकित्सा सेवाओं के कुशल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करके आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता को बढ़ाता है।
iv.उन्नत चिकित्सा उपकरण, RFID (रेडियो-फ्रीक्वेंसी IDentification) - कुशल रीपैकेजिंग और पुन: तैनाती के लिए टैग किया गया, क्यूब की प्रमुख विशेषताएं हैं।

<u>हाल के संबंधित समाचार:</u>
i.PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश (UP) के गाजियाबाद में साहिबाबाद RapidX स्टेशन पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर के 17 किलोमीटर (km) प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया।
ii.उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री (CM) योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) को राज्य जलीय जानवर घोषित किया है।

<u>लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के बारे में:</u>
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक– शेखिपुरम नारायणन सुब्रमण्यन
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

एयर इंडिया ने बेंगलुरु से मुंबई तक भारत की पहली एयरबस A350-900 फ्लाइट शुरू की

एयर इंडिया लिमिटेड ने भारत और एयर इंडिया का पहला **एयरबस A350-900** मॉडल विमान 'AI 589' लॉन्च किया है।

- फ्लाइट ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु (कर्नाटक) से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई (महाराष्ट्र) तक अपनी पहली उड़ान भरी।

एयरबस A350-900:
i.एयरबस A350 का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, **ज्योतिरादित्य M. सिंधिया** ने विंग्स इंडिया 2024 शिखर सम्मेलन में किया, जो 18 से 21 जनवरी 2024 तक बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित किया गया था।
ii.वर्तमान में फ्लाइट बेंगलुरु, चेन्नई (तमिलनाडु), नई दिल्ली (दिल्ली), हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों के बीच संचालित होगी।
iii.यह जून 2023 में एयर इंडिया द्वारा **एयरबस और बोइंग** के साथ 470 विमानों की आपूर्ति के लिए किए गए समझौते का एक हिस्सा है।

NHAI ने नेशनल हाईवे अनुभव को बढ़ाने के लिए 'वन व्हीकल वन FASTag' पहल शुरू की

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (**NHAI**) ने कई व्हीकल्स के लिए एक ही FASTag का उपयोग करने या एक विशेष व्हीकल के साथ कई FASTags को जोड़ने के उपयोगकर्ता के व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए **''वन व्हीकल, वनFASTag'** पहल शुरू की।

'वन व्हीकल, वन FASTag' पहल के बारे में:

i.नई पहल के तहत, FASTag उपयोगकर्ताओं को अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी FASTags को त्यागना होगा।

- केवल नवीनतम FASTag खाता सक्रिय रहेगा, क्योंकि पिछले टैग 31 जनवरी, 2024 के बाद निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे, भले ही उनके पास वैध शेष राशि हो।
- FASTag उपयोगकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिशानिर्देशों के अनुसार 'नो योर कस्टमर' (KYC) प्रक्रिया पूरी करने के साथ नवीनतम FASTag को पंजीकृत करना होगा।

ii.उल्लंघन की रिपोर्ट के बाद NHAI ने एक नई पहल की है:

- किसी विशेष व्हीकल के लिए एकाधिक FASTags जारी करना।
- RBI के आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना KYC के FASTag जारी किए जाते हैं।

iii.नई पहल टोल संचालन को अधिक कुशल बनाने और नेशनल हाईवे उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध & आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

FASTag के बारे में:

i.FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जो NHAI द्वारा संचालित है।

- इसे पहली बार भारत में **2014** में पेश किया गया था और जारी होने की तारीख से इसकी वैधता अवधि **5 वर्ष** है। NHAI ने **फरवरी 2021** में इसे प्रत्येक व्हीकल के लिए अनिवार्य कर दिया।

ii.यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (**RFID**) तकनीक का उपयोग करता है जो उपयोगकर्ताओं को बिना इंतजार किए या रुके टोल प्लाजा पर सरल और सहज क्रॉस-ओवर प्रदान करता है।

iii.FASTag (RFID टैग) व्हीकल की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को FASTag से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

PM नरेंद्र मोदी ने UP के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

25 जनवरी, 2024 को, भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश (UP) के बुलंदशहर ज़िले में रेल, सड़क, तेल और गैस और शहरी विकास & आवास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये 19,100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

रेल परियोजनाएँ:

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) पर न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के बीच 173 km लंबे डबल-लाइन विद्युतीकृत खंड का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों स्टेशनों से मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया गया।

- इसमें उच्च ऊंचाई वाले विद्युतीकरण के साथ **एक किलोमीटर की डबल-लाइन रेल सुरंग** है, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली सुरंग है, जो डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेनों के निर्बाध संचालन की सुविधा प्रदान करती है, जो माल गाड़ियों को DFC ट्रैक की ओर मोड़कर बेहतर पैसेंजर्स ट्रेन संचालन में योगदान देती है।

ii.मथुरा-पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग-दादरी खंड को जोड़ने वाली एक रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है जो राष्ट्रीय राजधानी की दक्षिणी-पश्चिमी और पूर्वी भारत के लिए रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेगी।

सड़क परियोजनाएँ:

PM मोदी ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 5000 करोड़ रुपये से अधिक की संचयी लागत से विकसित कई सड़क विकास परियोजनाओं को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

i.अलीगढ़ से भदवास फोर-लेन वर्क पैकेज-1 (राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)-34 के अलीगढ़-कानपुर खंड का हिस्सा)

ii.शामली होते हुए मेरठ से करनाल सीमा तक चौड़ीकरण (NH-709A)

iii.NH-709 AD पैकेज-II के शामली-मुजफ्फरनगर खंड को फोर लेन का बनाना।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एट ग्रेटर नोएडा:

i.प्रधानमंत्री (PM) गति शक्ति - मल्टी-मोडल कन्वेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित **'इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एट ग्रेटर नोएडा'** (IITGN) का उद्घाटन किया गया।

ii.747 एकड़ में **1,714 करोड़ रुपये** की लागत से बनी यह टाउनशिप रणनीतिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों के जंक्शन पर स्थित है, जिसके दक्षिण में पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और पूर्व में दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन है।

अन्य:

i.PM मोदी ने लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल) की 255 km लंबी टूंडला-गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया।

- इससे मथुरा और टूंडला में पंपिंग सुविधाओं और टूंडला, लखनऊ और कानपुर में डिलीवरी सुविधाओं के साथ बरौनी-कानपुर पाइपलाइन के टूंडला से गवारिया T-प्वाइंट तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में सहायता मिलेगी।

ii.लगभग **460 करोड़ रुपये** की लागत से सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण सहित पुनर्निर्मित **मथुरा सीवरेज स्कीम** का उद्घाटन किया गया। इस कार्य में मसानी में 30 मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज (MLD) STP का निर्माण, ट्रांस यमुना में मौजूदा 30 MLD और मसानी में 6.8 MLD STP का पुनर्वास & 20 MLD TTRO प्लांट (तृतीयक उपचार और रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट) का निर्माण शामिल है।

- PM ने मुरादाबाद (रामगंगा) सीवरेज सिस्टम & STP कार्यों (चरण I) का भी उद्घाटन किया। **लगभग 330 करोड़ रुपये** की लागत से निर्मित, इसमें 58 MLD STP , लगभग 264 km लंबा सीवरेज नेटवर्क और मुरादाबाद में रामगंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए नौ सीवेज पंपिंग स्टेशन शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने MP में भारत की पहली स्वस्थ & स्वच्छ फूड स्ट्रीट "PRASADAM" का उद्घाटन किया

7 जनवरी 2024 को, केंद्रीय स्वास्थ्य & परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश (MP) के उज्जैन में नीलकंठ वन, महाकाल लोक में भारत की पहली स्वस्थ & स्वच्छ फूड स्ट्रीट "PRASADAM" का उद्घाटन किया।

- उद्घाटन के दौरान MP के मुख्यमंत्री (CM) डॉ. मोहन यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

939 वर्ग मीटर में फैली कुल 17 दुकानों वाला PRASADAM, महाकालेश्वर मंदिर के भक्तों के लिए सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन विकल्प प्रदान करता है।

अन्य विख्यात लॉन्च:

i.केंद्रीय मंत्री ने स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट पहल के लिए आधिकारिक वेबसाइट और स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की रूपरेखा बताने वाली विवरणिका भी लॉन्च की।

ii.उन्होंने **मैनहिट ऐप** भी लॉन्च किया, जो मानसिक स्वास्थ्य की जांच की सुविधा प्रदान करने वाली एक पहल है।

iii.फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने उपभोक्ताओं को सरल परीक्षणों के साथ घर पर मिलावट से निपटने के लिए सशक्त बनाने के लिए "द DART बुक" जारी की।

iv.प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों के संचालन के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW) नामक एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी लॉन्च की गई।

PM नरेंद्र मोदी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया

28 जनवरी, 2024 को, भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट सभागार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) की हीरक जयंती (75वें वर्ष) समारोह का उद्घाटन किया।

- यह दिन 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

मुख्य विचार:

i.PM मोदी ने कई नागरिक-केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल - डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (SCR), डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट (https://www.sci.gov.in/) शुरू की।

ii.कार्यक्रम के दौरान, PM मोदी ने घोषणा की कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

iii.चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया **(CJI) धनंजय यशवंत चंद्रचूड़** की अध्यक्षता में एक **औपचारिक पीठ** SCI के हीरक जयंती वर्ष (2024) की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए बुलाई गई थी। पीठ में सभी सहयोगी न्यायाधीश शामिल थे।

- हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इस कार्यक्रम का हिस्सा थे।

नई पहल के बारे में:

i.डिजिटल SCR इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट (SC) के फैसलों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा।
इसमें 1950 के बाद से 36,308 मामलों सहित SC रिपोर्टों के सभी 519 खंड भी शामिल हैं। यह डिजिटल प्रारूप में, बुकमार्क, उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुली पहुंच के साथ उपलब्ध होगा।

ii.डिजिटल कोर्ट 2.0, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक पहल, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जिला अदालतों के न्यायाधीशों को अदालती रिकॉर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। यह वास्तविक समय के आधार पर भाषण को पाठ में स्थानांतरित करने के लिए आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) का भी उपयोग करता है।

iii.SC की नई वेबसाइट, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ पुन: डिज़ाइन की गई, द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) प्रारूप में उपलब्ध है।

अन्य प्रमुख प्रतिभागी:

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस (MoL&J), सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई; अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया , R वेंकटरमणी; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष; डॉ आदिश C अग्रवाल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सभापति मनन कुमार मिश्रा।

पृष्ठभूमि:

i.सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि "भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा।"

ii.SCI का उद्घाटन पुराने संसद भवन के चैंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ, जहां 1937 से 1950 तक भारत का संघीय न्यायालय स्थित था।

iii.पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया , हरिलाल J. कानिया ने 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन बैठक का नेतृत्व किया।

हाल के संबंधित समाचार:

i.मद्रास हाई कोर्ट (चेन्नई, तमिलनाडु) ने IRDAI को नियोक्ता के वाहनों के लिए निजी कार पॉलिसी जारी करते समय कर्मचारियों के लिए इनबिल्ट कवरेज के रूप में इंडियन मोटर टैरिफ 2002 के IMT-29 को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है।

ii.CJI धनंजय यशवंत (DY) चंद्रचूड़ को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा '2022 सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन (CLP) अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप' से सम्मानित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) के बारे में:

वर्तमान CJI–धनंजय यशवंत (DY) चंद्रचूड़

स्थापना- 28 जनवरी, 1950

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली

FESTIVAL

असम ने 14 वां चंद्रबी उत्सव 1 से 5 जनवरी 2024 तक मनाया

चंदुबी उत्सव एक वार्षिक 5 दिवसीय उत्सव है जो असम के चंदुबी झील (गुवाहाटी शहर से 64 km दूर) के किनारे नए साल के पहले दिन से आयोजित किया जाता है। **चंदुबी उत्सव का 14वां संस्करण 1 से 5 जनवरी 2024** तक आयोजित किया गया था।

- यह उत्सव असम के आदिवासी समुदायों जैसे राभा, गारो, गोरखा आदि की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है जो चंदुबी झील के पास रहते हैं।
- 2024 उत्सव का आयोजन राभा हसोंग स्वायत्त परिषद (RHAC) के तहत कामरूप जिले के राजापारा गांव के लोगों द्वारा किया गया था।

i.उत्सव के उद्घाटन में शिक्षक और कुहिपथ के निर्माता गौरीकांत भौयान द्वारा स्मारिका 'लोकिया' का विमोचन हुआ।

ii.उत्सव समारोह समिति ने पूरे उत्सव के दौरान विभिन्न जातीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें बागबोल, खुटीखेल और कई अन्य राभा जनजाति जातीय खेल प्रतियोगिताएं शामिल थीं।

उत्सव का उद्घाटन पलाशबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा सदस्य (MLA) हेमंगा ठाकुरिया ने किया।

गुजरात के CM भूपेन्द्र पटेल ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया

गुजरात के मुख्यमंत्री (CM) **भूपेन्द्रभाई पटेल** ने अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती रिवरफ्रंट, वल्लभ सदन में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया।

- यह महोत्सव 7 से 14 जनवरी 2024 तक अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा।
- यह महोत्सव हिंदू कैलेंडर में उन दिनों को चिह्नित करता है जब सर्दी गर्मियों में बदलने लगती है, जिसे मकर संक्रांति या उत्तरायण के रूप में जाना जाता है।
- इस महोत्सव में 55 देशों के 153 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पतंगबाज, 12 राज्यों के 68 राष्ट्रीय पतंगबाज और गुजरात के 23 शहरों के 865 पतंग प्रेमी शामिल हैं।

नोट: 1989 से, अहमदाबाद शहर ने उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी की है।

अरुणाचल प्रदेश ने 9वां संस्करण पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया

पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव (**PPHF**) का **9वां** संस्करण 18 से 20 जनवरी, 2024 तक अरुणाचल प्रदेश (**AR**) के पक्के-केसांग जिले के सेइजोसा में मनाया गया।

- इसे "डोमुतोह दोमुतोह, पागा हम दोमुतोह" **थीम** के तहत आयोजित किया गया था, जिसका न्यीशी भाषा में अर्थ 'लेट आवर होर्नबिल्स रीमैन' है।

प्रमुख लोग:

उद्घाटन समारोह में AR के उप मुख्यमंत्री (**CM**) चाउना मीन और न्यीशी एलीट सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर ताना शोरेन ने भाग लिया।

PPHF के बारे में:

i.PPHF महोत्सव पहली बार **2015** में AR के पक्के टाइगर रिजर्व (**PTR**) में हॉर्नबिल के संरक्षण में निवासी **न्यीशी जनजाति** द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचानने के लिए मनाया गया था।

- यह AR में एकमात्र वन्यजीव संरक्षण महोत्सव है।

ii.2019 में, PPHF को CM पेमा खांडू द्वारा राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया गया था।

iii. यह महोत्सव क्षेत्र के मूल लोगों को आय का एक वैकल्पिक स्रोत भी प्रदान करता है जो मुख्य रूप से शिकार और लॉगिंग पर निर्भर हैं।

iv. महोत्सव का उद्देश्य धन जुटाना भी है PTR के बारे में जागरूकता, और हॉर्नबिल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस उत्सव ने प्रदूषण से निपटने, वन्यजीवों की रक्षा करने और पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने के लिए विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करने में वर्षों से सकारात्मक प्रभाव डाला।

PPHF 2024:

i.PPHF 2024 का लक्ष्य है इन हॉर्नबिल्स को संरक्षित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालें।

ii.पक्षियों को देखना, तितली की सैर, भालू की सैर, हॉर्नबिल बसेरा स्थल का दौरा, लघु फिल्म स्क्रीनिंग, पैनल चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, नदी और गाँव की सैर, स्थानीय आदिवासियों के प्रदर्शन जैसी गतिविधियाँ उत्सव में खेल और नृत्य आयोजित किए गए।

अतिरिक्त जानकारी:

PTR में हॉर्नबिल की चार प्रजातियां (अर्थात् ब्रीथेड, ग्रेट इंडियन, ओरिएंटल पाइड और लुप्तप्राय रूफस-नेक्ड) पाई जाती हैं।

OTHER NEWS

उत्तर प्रदेश लखनऊ में भारत का पहला AI सिटी बनाने के लिए तैयार है

उत्तर प्रदेश (**UP**) AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए **लखनऊ** में **भारत का पहला आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी** बनाने के लिए तैयार है। AI सिटी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करने वाला एक केंद्र होगा।

i.परियोजना की नोडल एजेंसी, **U.P. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड** ने AI सिटी के निर्माण और संचालन के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स को आमंत्रित करते हुए रुचि की अभिव्यक्ति (**EoI**) जारी की है।

- U.P. इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, UP सरकार की एक इकाई।

ii.UP सरकार परियोजना के लिए नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी।

iii.वित्तीय प्रोत्साहन: IT पार्कों के लिए 20 करोड़ रुपये तक 25% का एकमुश्त पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) समर्थन और IT सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये और IT और ITeS नीति, 2022 के अनुसार 100% मोहर शुल्क छूट है।

गुजरात भारत की 'पेट्रो कैपिटल' के रूप में उभरा

भरूच जिले के दहेज में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी और ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड (OPaL) के अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति के कारण गुजरात को भारत की 'पेट्रो कैपिटल' के रूप में मान्यता दी गई है।

RIL-जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स:

i.जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स सिंगल-साइट रिफाइनरी है।

ii.रिफाइनरी प्रति दिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रसंस्करण कर सकती है।

iii.रिफाइनरी का कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 21.1 है जो दुनिया में सबसे अधिक है।

iv.जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इकाइयाँ, जैसे फ्लुइडाइज़्ड कैटेलिटिक क्रैकर (FCC), कोकर, एल्काइलेशन, पैराक्सिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, रिफाइनरी ऑफ-गैस क्रैकर (ROGC) और पेटकोक गैसीफिकेशन प्लांट्स हैं।

v.रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना 2000 में हुई थी।

OPaL रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स:

i.OPaL दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक है।

ii.यह तेल और प्राकृतिक गैस निगम **(ONGC)**, भारतीय गैस प्राधिकरण **(GAIL)** & गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड **(GAIL)** के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) है।

iii.रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स 14 लाख टन पॉलिमर और 5 लाख टन रसायनों का उत्पादन कर सकता है जो विभिन्न अपस्ट्रीम प्रक्रियाओं में मूल्य जोड़ता है।

iv.OPaL की स्थापना 2006 में हुई थी।

नोट: ONGC और शेल इंडिया जैसी अन्य पेट्रोकेमिकल कंपनियां भी गुजरात के तेल उत्पादन में योगदान देती हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

i.दहेज का PCPIR, PCPIR नीति 2007 के तहत भारत सरकार (GoI) द्वारा घोषित चार PCPIR में से एक है।

- अन्य तीन विशाखापत्तम-काक्कीनाडा (आंध्र प्रदेश), पारादीप (ओडिशा) और कुड्डालोर-नागापट्टिनम (तमिलनाडु) हैं।

ii.VGGS का 10वां संस्करण, जिसका थीम 'गेटवे टू द फ्यूचर' है, जो 10-12 जनवरी 2024 को होने वाला है, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश और सहयोग को और बढ़ावा देगा।

वियतनाम के लैम डोंग और भारत के लेह लद्दाख के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन सहयोग लॉन्च किया गया

वियतनाम में लैम डोंग प्रांत और लद्दाख के लेह क्षेत्र में, भारत ने आधिकारिक तौर पर वियतनाम के दा लाट में "लद्दाख अनवील्ड" थीम के साथ एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन सहयोग पहल लॉन्च की।

- यह आयोजन इन दो प्रतिष्ठित क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है।

उपस्थित गणमान्य व्यक्ति:

लॉन्च के समय उपस्थित गणमान्य लोगों में फाम S(लैम डोंग प्रांत की पीपुल्स कमेटी के उपाध्यक्ष), गुयेन टुंग कीन (वियतनाम के संस्कृति, खेल, पर्यटन विभाग के निदेशक), एडवोकेट ताशी ग्यालसन (मुख्य कार्यकारी पार्षद और अध्यक्ष, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) शामिल थे।

प्रमुख बिंदु:

i.दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के अद्वितीय स्थलों को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई।

ii.लैम डोंग प्रांत एक संभावित पर्यटन स्थल है जो अपने समशीतोष्ण जलवायु, प्राकृतिक परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है।

iii.सैमटेन हिल्स डालाट, एक राजसी बौद्ध विरासत निर्माण, जो वियतनाम के लैम डोंग की समृद्धि को प्रदर्शित करता है, भी इस प्रांत में मौजूद है।

- यह स्थान, वियतनाम फेडरेशन ऑफ UNESCO एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित वज्रयान बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थान है, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रार्थना चक्र शामिल है।

iv.यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भविष्य के सहयोग और पारस्परिक समृद्धि की नींव रखता है।

लद्दाख के बारे में:

उपराज्यपाल - B.D. मिश्रा

राष्ट्रीय उद्यान - हेमिस राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभ्यारण्य - चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य

विंग्स इंडिया 2024 की मुख्य विशेषताएं: सिविल एविएशन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित हुआ

यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, ज्योतिरादित्य M. सिंधिया ने 18 से 21 जनवरी 2024 तक हैदराबाद, तेलंगाना के बेगमपेट एयरपोर्ट पर एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो-विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया।

- शो की थीम **"कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल: सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन @2047"** थी।
- सिविल एविएशन मंत्री ने विंग्स इंडिया 2024 के पहले दिन भारत और **एयर इंडिया के पहले एयरबस A350 विमान** का भी उद्घाटन किया।

विंग्स इंडिया 2024:

i.कार्यक्रम के दौरान भारतीय एयरक्राफ्टन क्षेत्र के तीन A- एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एंड अफ्फोर्डेबिलिटी को दोहराया गया

ii.विंग्स इंडिया 2024 में प्रमुख घोषणाएँ:

- FICCI और KPMG द्वारा सिविल एविएशन पर संयुक्त ज्ञान पत्र का विमोचन
- UDAN 5.3 का लॉन्च
- अधिक हवाई जहाजों की खरीद के साथ एयरबस-एयर इंडिया प्रशिक्षण केंद्र का लॉन्च और आने वाले वर्षों में 10 फ्लाइट सिमुलेटर और 10,000 पायलटों को प्रशिक्षित करने के साथ गुरुग्राम में एक फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- एयरबस मैन्युफैक्चरिंग ने TATA ASL और महिंद्रा एयरोस्पेस स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अधिक पायलटों को बढ़ावा देने के लिए अनुबंध किया।
- GMR (ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव) और IndiGo ने एयरोस्पेस उद्योग में टिकाऊ प्रशिक्षण विकसित करने में कई पैटर्न के साथ सहयोग करने के लिए एक कंसोर्टियम पर भी हस्ताक्षर किए।

विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स & इंडस्ट्री (**FICCI**) ने 18 जनवरी 2024 को होटल ताज कृष्णा, हैदराबाद में एक अवार्ड्स समारोह के दौरान सिविल एविएशन क्षेत्र में "विंग्स इंडिया अवार्ड्स" के **चौथे संस्करण** की घोषणा की। समारोह का आयोजन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन और FICCI के सहयोग से किया गया था, यह कार्यक्रम द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है।

एयरपोर्ट्स श्रेणी में अवार्ड्स	
अवार्ड्स	**विजेता**
एयरपोर्ट ऑफ द ईयर (जॉइंट अवार्ड्स)	• बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) • दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट)
>25 MPPA(मिलियन पैसेंजर्स पैर एनम)ट्रैफिक	बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (कर्नाटक)

10-25 MPPA ट्रैफिक	GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट)
5-10 MPPA ट्रैफिक	डाबोलिम एयरपोर्ट (गोवा)
<5 MPPA ट्रैफ़िक	मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (कर्नाटक)
इनोवेशन चैंपियन	मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट) (महाराष्ट्र)
सस्टेनेबिलिटी चैंपियन	दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
एयरलाइंस श्रेणी में अवार्ड्स	
एयरलाइन ऑफ द ईयर	विस्तारा-टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड
इंटरनेशनल कनेक्टिविटी	एयर इंडिया
डोमेस्टिक कनेक्टिविटी	InterGlobe एविएशन लिमिटेड (IndiGo)
रीजनल कनेक्टिविटी	एलायंस एयर
इनोवेशन चैंपियन	विस्तारा-टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड
सस्टेनेबिलिटी चैंपियन	एयर इंडिया एक्सप्रेस
बेस्ट कार्गो सर्विसेज अवार्ड	स्काईवेज़ एयर सर्विसेज
स्टेट चैंपियन अवार्ड्स	
आउटस्टैंडिंग परफॉरमेंस इन सिविल एविएशन	उत्तर प्रदेश
मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट	अरुणाचल प्रदेश
लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स	
डिस्टिंगुइश्ड वीमेन इन एविएशन	**तुलसी N मीरचंदानी**, ब्लू डार्ट के पूर्व MD
अन्य अवार्ड्स विजेता	

बेस्ट एविएशन सर्विस प्रोवाइडर	GMR ग्रुप
बेस्ट फ्यूल सर्विसेज	इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड
बेस्ट एयरो एकादमी	GMR एविएशन एकादमी
बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर	विज़ फ्रेट

भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एयरक्राफ्ट सीट विंग्स इंडिया 2024 में लॉन्च की गई

बेंगलुरु स्थित इंजीनियरिंग कंपनी टाइमटूथ ने विंग्स इंडिया 2024 में भारत की पहली एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स सीट लॉन्च की है। सीटों का निर्माण एप्सिलॉन एयरोस्पेस के सहयोग से किया गया है जिसने सीटों के लिए कवर और कुशन डिजाइन किए हैं।

- सीटें ITSO C39c मानकों के अनुसार डिजाइन की गई हैं और हिंदुस्तान (डोर्नियर) 228 (DGCA द्वारा हाल ही में प्रमाणित) जैसे एयरक्राफ्ट में उपयोग के लिए तैयार हैं।
- टाइमटूथ के CEO अमिताव चौधरी हैं|
- ITSO C127c के साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सीटें पहले से ही पाइपलाइन में हैं

अब तक, भारत में पंजीकृत हवाई यात्रा कंपनियों के स्वामित्व या संचालन वाले एयरक्राफ्ट की 100% सीटें आयात की जाती हैं।

AIR INDIA EXPRESS ने विंग्स इंडिया 2024 में कलमकारी से प्रेरित टेल पैटर्न वाले नए एयरक्राफ्ट का अनावरण किया

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक नए एयरक्राफ्ट, VT-BXH का अनावरण किया, जो कलमकारी से प्रेरित टेल पैटर्न वाला एक बोइंग 737-8 एयरक्राफ्ट है जो अपनी टेल कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता है।

i.अक्टूबर 2023 में, इसने 'पैटर्न ऑफ इंडिया' लॉन्च किया, जहां प्रत्येक नए एयरक्राफ्ट के टेल फिन पर विभिन्न कला रूपों को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- कलमकारी आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक भारतीय कला है जिसमें 'कलम' या लकड़ी के ब्लॉक नामक कलम जैसे उपकरण का उपयोग करके कपड़े पर हाथ से पेंटिंग या ब्लॉक-प्रिंटिंग शामिल है। डिज़ाइन दोहराव और समरूपता में है.

ii.9 कला डिजाइन में शामिल हैं

- गुजरात से बंधनी और पटोला
- असम से गमोसा
- पश्चिम बंगाल से जामदानी
- कश्मीर से जामावार
- पंजाब से फुलकारी
- तमिलनाडु से कांजीवरम
- उत्तर प्रदेश के बनारसी
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कलमकारी

अकासा एयर ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

इस समझौता ज्ञापन (MoU) के साथ, अकासा एयर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परिचालन शुरू करने वाली दूसरी एयरलाइन बन जाएगी।

- पहली एयरलाइन IndiGo है।

- उड़ान संचालन के लिए एयरपोर्ट का पहला चरण 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

एयरबस हेलीकॉप्टर, हेलिगो ने H145 बेड़े के लिए सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए

एयरबस और हेलिगो चार्टर प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में अपतटीय और तटवर्ती दोनों परिचालनों में उपयोग किए जाने वाले छह एयरबस H145 हेलीकॉप्टरों के लिए एक सर्विस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- HCare इनिशियल 5 साल का प्रति घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है।
- इसके साथ हेलिगो भारत में सबसे बड़े H145 बेड़े का दावा करेगा।
- इस सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट से हेलिगो का रखरखाव खर्च कम हो जाएगा।
- हेलिगो चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में ONGC के अपतटीय परिचालन के लिए एयरबस हेलीकॉप्टरों के 5-ब्लेड वाले H145 बेड़े प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी।

स्वदेशी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विकास को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने CSIR-IIP के साथ साझेदारी की

भारत में स्वदेशी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) का टेस्टिंग और योग्यता प्राप्त करने के लिए एयरबस और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (CSIR-IIP) के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे भारतीय एयरोस्पेस उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन में मदद मिलेगी।

- SAF का उत्पादन एक नए HEFA प्रौद्योगिकी मार्ग का उपयोग करके किया जाएगा और इसे स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाएगा।
- एविएशन क्षेत्र 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बना रहा है
- MoU के तहत, CSIR-IIP नए मार्ग के तहत फ्यूल गुणों और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन करेगा, जबकि एयरबस नए फ्यूल मूल्यांकन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेगा, फ्यूल टेस्टिंग और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के ज्ञान को साझा करेगा।

नोट: HEFA (हाइड्रो प्रोसेस्ड एस्टर और फैटी एसिड), जिसे HVO (हाइड्रोट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल) भी कहा जाता है, एक नवीकरणीय डीजल फ्यूल है जिसे वनस्पति तेलों और वसा की एक विस्तृत श्रृंखला से उत्पादित किया जा सकता है। HEFA या HVO शब्द का उपयोग इन बायोजेनिक हाइड्रोकार्बन-आधारित नवीकरणीय बायो फ्यूल के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है।

द विंग्स इंडिया 2024 के बारे में

- इस कार्यक्रम में दो दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक आम जनता ने भाग लिया, जिससे यह एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन कार्यक्रम बन गया
- एक प्रमुख आकर्षण एयर और ड्रोन शो के साथ-साथ 25 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का स्थिर प्रदर्शन था
- एयर शो में भारतीय वायु सेना के चार सारंग हेलीकॉप्टर, UK की मार्क जेफ्रीज़ टीम के चार एयरक्राफ्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 मैक्स 8 ने प्रभावशाली कम फ्लाई-बाय और जटिल युद्धाभ्यास को अंजाम दिया।

UDAN स्कीम की उपलब्धियां

सिविल एविएशन मंत्री ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान UDAN स्कीम की मदद से भारत के एविएशन क्षेत्र की उपलब्धि का वर्णन किया। UDAN को **2016 में** मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन के तहत एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के रूप में लॉन्च किया गया था।

- डोमेस्टिक पैक्स (पैसेंजर्स, जिन्हें आमतौर पर एविएशन शब्दावली में पैक्स के रूप में जाना जाता है) की कुल संख्या 2014 में 60 मिलियन से बढ़कर 2020 में 143 मिलियन हो गई, जो 14.5% की CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ रही है और 2023 में 150 मिलियन के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है
- 2014 से 2020 तक इंटरनेशनल पैसेंजर्स की संख्या 6.1% की CAGR से बढ़ी थी

- FY 2019 तक 15 वर्षों में भारतीय एयरपोर्ट्स द्वारा प्रबंधित डोमेस्टिक कार्गो मात्रा में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इंटरनेशनल कार्गो मात्रा में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- सैद्धांतिक तौर पर 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 12 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स चालू हो चुके हैं।
- PM की फ्लैगशिप स्कीम RCS-UDAN (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम- उड़े देश का आम नागरिक) के तहत, टियर -3 और टियर -4 में 76 एयरपोर्ट्स और देश के अन्य दूरस्थ कोने को 1.32 करोड़ से अधिक लोगों के साथ चालू किया गया है 2.5 लाख से अधिक फ्लाइट्स में इस योजना से 1.32 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
- सरकार ने लगभग 3,100 करोड़ रुपये की VGF (वायबिलिटी गैप फंडिंग) प्रदान की थी, 1300 UDAN मार्ग प्रदान किए थे और स्कीम के तहत 517 मार्गों का संचालन किया था।
- देश में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी करना 2022 में 1165 CPL (कमर्शियल पायलट लाइसेंस) से 40% बढ़कर 2023 में 1,622 CPL हो गया है।
- 2047 तक, भारत के पास एक एविएशन सिस्टम होगी जो 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का समर्थन करेगी।
- GAGAN (GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन) का उपयोग करके हेलीकॉप्टर-विशिष्ट निम्न-स्तरीय IFR मार्ग को रोलआउट करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन (MoCA) के बारे में:

यूनियन मिनिस्टर : ज्योतिरादित्य सिंधिया (राज्यसभा-मध्य प्रदेश)

मिनिस्टर ऑफ स्टेट: विजय कुमार सिंह (निर्वाचन क्षेत्र - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश)

J&K PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT बन गया

जम्मू और कश्मीर (J&K) प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY) को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश (**UT**) बन गया है। PMVY के तहत 'दारजी शिल्प' में 30 प्रशिक्षुओं (विश्वकर्मा) के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) शोपियां, J&K में किया गया।

प्रमुख लोग: प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन विर्चुअलि J&K के उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के सचिव अतुल कुमार तिवा ने किया।

PM विश्वकर्मा योजना (PMVY) के बारे में:

i.PM विश्वकर्मा योजना (PMVY) सितंबर 2023 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) है।

ii.इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है

iii.योजना की टैगलाइन **'सम्मान सामर्थ्य समृद्धि'** है।

iv.लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

v.यह योजना **18 पारंपरिक शिल्पों** को कवर करेगी।

- बढ़ई, नाव बनाने वाला, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाला, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार & पत्थर तोड़ने वाला, मोची (जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर), मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कॉयर बुनकर, गुड़िया & खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता।

vi.यह योजना 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।

vii.यह योजना डिजिटल लेनदेन और विपणन सहायता के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।

viii.इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) से FY28 तक पांच वर्षों में 30 लाख परिवारों को कवर करना है

प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में:

i.प्रशिक्षुओं को 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ii.प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा दिया जाएगा और 15,000 रुपये का मुफ्त आधुनिक टूलकिट मिलेगा।

फिनमिन ने चीन से आयातित 'व्हील लोडर' & चीन, ओमान से जिप्सम बोर्ड पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाया

वित्त मंत्रालय ने चीन से 'व्हील लोडर' के आयात पर 5 साल की अवधि के लिए निश्चित एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाया है। ड्यूटी दरें, **18.84%** से **82.71%** तक, निर्माता और विशिष्ट वस्तुओं के आधार पर भिन्न होती हैं।

- यह ड्यूटी कंप्लीट बिल्ड यूनिट (CBU) और सेमी-नॉक्ड डाउन (SKD) फॉर्म में आयात पर, न कि कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) फॉर्म पर लागू होगा।

इसने चीन और ओमान से कम से कम एक तरफ लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइल्स (जिसे PVC जिप्सम टाइल्स, जिप्सम सीलिंग टाइल्स या सीलिंग टाइल्स के रूप में भी जाना जाता है) पर पांच साल के लिए निश्चित एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाया है।

- चीन से आयात के मामले में यह **23.46-47.62** अमेरिकी डॉलर **प्रति टन** और ओमान के लिए **71.80-91.42 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक** टन के बीच होगा।

महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया

महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व (**PRT**) को रात के आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के पहले **डार्क स्काई पार्क** और एशिया के पांचवें पार्क के रूप में नामित किया गया है, जिससे यह स्थान खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए आदर्श बन गया है।

- डार्क स्काई प्लेस प्रमाणन प्रकाश नीति, अंधेरे आकाश के अनुकूल रेट्रोफिट्स, आउटरीच और शिक्षा और रात के आकाश की निगरानी पर केंद्रित है।
- जिला योजना समिति (DPC) निधि की नवप्रवर्तन योजना के तहत एक रात्रि वेधशाला का भी उद्घाटन किया गया है। ज्ञातव्य है कि बाघोली के निकट का क्षेत्र तारा-दर्शन हेतु आरक्षित किया गया है।
- पेंच टाइगर रिजर्व, जिसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, दो राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है।

गुजरात के कच्ची खरेक फल को भौगोलिक संकेत टैग मिला

कच्ची खरेक या कच्छी खजूर, गुजरात में कच्छ की स्वदेशी खजूर किस्म को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत चेन्नई (तमिलनाडु) स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत (**GI**) टैग मिला है।

- कच्ची खरेक **'कृषि'** के माल प्रकार के तहत पंजीकृत है।

कच्ची खरेक के बारे में:

i."कच्ची खरेक" **खलल** (ताजा अवस्था) में काटे गए खजूर का उत्पाद है, जब फल अपने सक्रिय रंग (लाल, पीले या इसके प्रकार) में होते हैं।
ii.फल पोषक तत्वों (विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट,फैट, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन) और उच्च कैलोरी मान से भरपूर होते हैं।
iii.गुजरात सरकार के अनुसार, कच्छ में 19,251 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर की खेती की जाती है, जो कि गुजरात के कुल 20,446 हेक्टेयर खजूर की खेती क्षेत्र का 94 प्रतिशत है।

प्रमुख बिंदु:

i.कच्ची खरेक कृषि उत्पाद के तहत गिर केसर आम (2011) के बाद GI टैग पाने वाला गुजरात का **दूसरा फल** बन गया है।

ii.GI टैग वाली कच्ची खरेक से कच्छी खजूर की ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा और शुष्क और अर्ध-शुष्क कच्छ क्षेत्र में खजूर उगाने वाले हजारों किसानों को लाभ होगा।

GI टैग के बारे में:

i.GI उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है।

भारत मत्स्य प्रबंधन पर FAO COFI उप-समिति का पहला उपाध्यक्ष बना

भारत को संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन (**FAO**) की मत्स्य पालन समिति (**COFI**) की मत्स्य पालन प्रबंधन पर उप-समिति (SCFM) के **पहले उपाध्यक्ष** के रूप में चुना गया है।

चुनाव:

i.SCFM ब्यूरो के चुनाव 15 से 18 जनवरी 2024 तक रोम, इटली में FAO मुख्यालय में आयोजित उप-समिति के पहले सत्र के दौरान आयोजित किए गए थे।

ii.ब्यूरो में उप-समिति के अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और 5 अन्य उपाध्यक्ष शामिल हैं, सभी **2 साल के कार्यकाल** के लिए चुने गए हैं।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल:

i.भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव J. बालाजी ने किया।

ii.डॉ. बालाजी को SCFM के आने वाले ब्यूरो के **पहले उपाध्यक्ष** के रूप में चुना गया था।

प्रमुख बिंदु:

i.वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि के रूप में, भारत की भागीदारी मत्स्य पालन प्रशासन और प्रबंधन पर वैश्विक चर्चा में एक संतुलित और व्यापक परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करती है। यह विशेष रूप से कारीगर और छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करता है।

ii.भारत 57 वर्षों में पहली बार **मत्स्य पालन के कब्जा पर FAO मत्स्य पालन ब्यूरो** के सदस्य के रूप में काम करेगा।

मत्स्य पालन प्रबंधन पर उप-समिति के बारे में:

i.SCFM की स्थापना 5 से 9 सितंबर, 2022 तक रोम, इटली में FAO COFI के 35वें सत्र के दौरान की गई थी।

ii.COFI FAO परिषद की एक सहायक संस्था है। FAO सम्मेलन ने 1965 में अपने 13वें सत्र में COFI की स्थापना की।

सदस्यता: उप-समिति FAO के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है। गैर सदस्य देश जो संयुक्त राष्ट्र (UN) या UN की विशेष एजेंसियों के सदस्य हैं, वे उप-समिति में प्रवेश मांग सकते हैं।

कार्य:

i.SCFM मत्स्य प्रबंधन मुद्दों पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह FAO के मिशन से जुड़े तकनीकी और नीतिगत मामलों से संबंधित है।

ii.उप-समिति के प्राथमिक कार्यों में जिम्मेदार मत्स्य पालन के लिए FAO आचार संहिता को आगे बढ़ाने के लिए मत्स्य प्रशासन और प्रबंधन पर आवश्यक तकनीकी और नीति मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है।

iii.यह मत्स्य पालन से संबंधित मामलों में अपनी भागीदारी को बढ़ाते हुए, एक्वाकल्चर पर उप-समिति और मछली व्यापार पर उप-समिति के साथ मिलकर सहयोग करता है।

नोट:

i.भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% हिस्सा है। 28 मिलियन से अधिक अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन के साथ इसे मछली पकड़ने वाले शीर्ष देशों में से एक माना जाता है।

ii.चीन दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है जिसके बाद इंडोनेशिया है।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के बारे में:

महानिदेशक– डॉ. क्यू डोंगयु

मुख्यालय– रोम, इटली

स्थापित– 1945

DRDO का 66वां स्थापना दिवस - 1 जनवरी 2024

रक्षा अनुसंधान & विकास संगठन (**DRDO**), रक्षा मंत्रालय (MoD) की अनुसंधान और विकास (R&D) शाखा, प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस या राइसिंग डे मनाती है।

1958 में गठित DRDO ने **1 जनवरी 2024** को अपना **66वां स्थापना दिवस** मनाया।

DRDO का गठन:

DRDO का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से ही कार्यरत तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDE) और तकनीकी विकास & उत्पादन निदेशालय (DTDP) को रक्षा विज्ञान संगठन (DSO) के साथ मिलाकर किया गया था।

वर्तमान में, DRDO 52 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (**DYSL**) का एक नेटवर्क है।

2024 के कार्यक्रम:

66वां DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के **अवदी** (भारत के बख्तरबंद वाहन और गोला-बारूद डिपो) में लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (**CVRDE**) के ARJUN सभागार में मनाया गया।

रक्षा R&D विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर V कामत ने नई दिल्ली में DRDO बिरादरी को संबोधित किया।

लॉन्च:

DRDO अध्यक्ष ने विस्फोटकों और संबंधित इमारतों की स्थिति को स्वचालित करने के लिए पुणे (महाराष्ट्र) स्थित प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (**HEMRL**) द्वारा विकसित **क्वांटिटी-डिस्टेंस सॉफ्टवेयर** भी लॉन्च किया।

- यह सॉफ्टवेयर सभी MoD प्रतिष्ठानों के लिए एक आवश्यक उपकरण है जो इष्टतम समय में और अधिक सटीकता के साथ विस्फोटक-संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है।

2023 में DRDO की मुख्य विशेषताएं:

i.DRDO को कई DRDO द्वारा विकसित प्रणालियों को शामिल करने के लिए लगभग 1,42,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता की स्वीकृति (**AoN**) प्राप्त हुई।

- यह किसी भी वर्ष में DRDO द्वारा विकसित प्रणालियों को दिया गया अब तक का सबसे अधिक स्वीकृत है।

ii.घरेलू विकसित प्रणालियों के 1,650 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) भारतीय उद्योगों को सौंप दिए गए हैं।

- 2023 में, DRDO उत्पादों के निर्माण के लिए स्वदेशी कंपनियों के साथ 109 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग समझौते (LAToT) पर हस्ताक्षर किए गए।

iii.DRDO ने 141 से अधिक पेटेंट दायर किए और उनमें से 212 स्वीकृत किए गए।

TDF संवर्द्धन:

प्रौद्योगिकी विकास कोष (**TDF**) और संबद्ध योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु ऊर्जा विभाग (**DAE**) के पूर्व सचिव डॉ. काकोडकर और NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के सदस्य डॉ. सारस्वत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

उद्देश्य: संयुक्त राज्य अमेरिका (**USA**) में रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी (DARPA) द्वारा अपनाए गए मॉडल के समान अत्याधुनिक अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करना।

रक्षा अनुसंधान & विकास संगठन (DRDO) के बारे में:

अध्यक्ष– डॉ समीर V कामत

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली

EPFO ने उच्च पेंशन विकल्पों के लिए वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी

3 जनवरी 2024 को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (**EPFO**) ने नियोक्ताओं को उच्च पेंशन विकल्पों के वेतन विवरण ऑनलाइन अपलोड करने के लिए **31 दिसंबर 2023** से **31 मई 2024** तक पांच महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

- इसकी जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी।

विस्तार के पीछे कारण:

विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक लंबित आवेदनों के साथ, EPFO ने इन बकाया प्रस्तुतियों को संसाधित करने में नियोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए एक विस्तार को मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि:

i.अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जवाब में, EPFO ने फरवरी 2023 में 3 मई, 2023 की प्रारंभिक समय सीमा के साथ पेंशन विकल्प सत्यापन के लिए एक ऑनलाइन आवेदन सुविधा शुरू की।

ii.कर्मचारियों के अभ्यावेदन के बाद, समय सीमा 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई और बाद में 11 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दी गई।

iii.नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के बाद समय सीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बारे में

EPFO श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी– नीलम शमी राव

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली

स्थापना- 1952

अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों: आदि केकिर, हस्तनिर्मित कालीन & वांचो शिल्प को GI टैग मिला

चेन्नई, तमिलनाडु (TN) स्थित भौगोलिक संकेत पंजी कार्यालय ने **अरुणाचल प्रदेश (AR)** के **3 स्वदेशी उत्पादों** अर्थात् **आदि केकिर** (अदरक), **हस्तनिर्मित कालीन** (तिब्बती निवासियों द्वारा), और **वांचो लकड़ी के शिल्प** को भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया है।

i.3 नए GI उत्पादों को शामिल करने के साथ, अरुणाचल प्रदेश में अब कुल **8 GI उत्पाद** हैं।

ii.अन्य 5 उत्पाद: अरुणाचल (वाक्रो) ऑरेंज; इदु मिश्मी टेक्सटाइल; खॉ ताई (खम्ती चावल); याक चुरपी और तांगसा टेक्सटाइल हैं।

3 नए GI उत्पादों के बारे में:

GI उत्पाद	माल का प्रकार
अरुणाचल प्रदेश आदि किकर (अदरक)	कृषि
अरुणाचल प्रदेश हस्तनिर्मित कालीन	हस्तशिल्प
अरुणाचल प्रदेश वांचो लकड़ी शिल्प	हस्तशिल्प

उत्पाद के बारे में:

i.आदि किकर एक स्वादिष्ट अदरक का प्रकार है जो AR के पूर्वी सियांग, सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में उत्पादित होता है।

ii.AR भर में तिब्बती शरणार्थियों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित कालीन अपने डिजाइन, रूपांकनों और बनावट के लिए जाने जाते हैं।

iii.वांचो लकड़ी शिल्पमें सिर के आकार के कटोरे के साथ तंबाकू पाइप और पीने के मग शामिल हैं जो सिर ले जाने वाले योद्धाओं को चित्रित करते हैं।

- वांचो समुदाय द्वारा बनाई गई लकड़ी की वस्तुओं में जटिल विवरण के साथ भगवान बुद्ध, जानवरों और गुड़िया की मूर्तियां भी शामिल हैं।

ध्यान देने योग्य बातें:

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (**NABARD**) 'वोकल फॉर लोकल' के तहत AR सरकार की पहल का समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अब तक NABARD द्वारा समर्थित ऐसे 18 उत्पादों में से 6 को GI पंजीकरण प्राप्त हो चुका है।

पश्चिम बंगाल में हथकरघा साड़ियों की तीन किस्मों & ओडिशा के 7 उत्पादों को GI टैग मिला

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के तहत भौगोलिक संकेत पंजी कार्यालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की 3 हथकरघा साड़ियों को भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया है, अर्थात् **तांगेल, कोरियाल** और **गराड** को कपड़ा के सामान के तहत भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुए हैं।

- तांगेल साड़ियाँ नादिया और पूर्व बर्धमान जिलों में बुनी जाती हैं, जबकि कोरियाल और गारद मुर्शिदाबाद और बीरभूम में बुनी जाती हैं।

साड़ियों के बारे में:

i.तांगेल सूती साड़ियाँ: महीन गिनती, रंगीन धागे का उपयोग करके अतिरिक्त ताना डिज़ाइन से सजी; इसका नाम वर्तमान बांग्लादेश के तांगेल जिले के नाम पर रखा गया है।

ii.कोरियाल साड़ियाँ: सफेद या क्रीम रंग में भव्य रेशम; बॉर्डर और पल्लू में बनारसी साड़ियों जैसे भारी सोने और चांदी के अलंकरण हैं।

iii.गराड सिल्क साड़ियाँ: सादा सफेद या मटमैला शरीर, अलंकृत रंग का बॉर्डर, धारीदार पल्लू; पूजा के दौरान पारंपरिक रूप से पहना जाता है; मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में शुद्ध रेशम से हाथ से बुना हुआ।

ओडिशा के 7 उत्पादों को GI टैग

भौगोलिक संकेत पंजी कार्यालय ने ओडिशा के 7 विशिष्ट उत्पादों को GI टैग भी प्रदान किया। इनमें दो स्थानीय खाद्य पदार्थ, तीन कृषि उत्पाद और वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए प्रत्येक में एक लांजिया सौरा चित्रकारी, डुंगरिया कोंध कढ़ाई वाला शॉल, गजपति खजूर का ताड़, ढेंकनाल मगजी, मयूरभंज काई चटनी, नयागढ़ कांतेइमुंडी बैंगन और कोरापुट कालाजीरा चावल शामिल हैं।

- इसके साथ ही ओडिशा को अब तक 25 GI टैग मिल चुके हैं।

उत्पादों के बारे में:

i.लांजिया सौरा कला रूप: यह ओडिशा के रायगड़ा जिले में एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) 'लांजिया सौरा' जनजाति से संबंधित है।

- ये मूल रूप से आदिवासी घरों के बाहरी भित्तिचित्रों में हैं जिनमें लाल मैरून पृष्ठभूमि पर सफेद चित्रकारी हैं।

ii.डुंगरिया कोंध कढ़ाई शॉल: रायगढ़ा के नियामगिरि पहाड़ियों में PVTG, डुंगरिया कोंध और कालाहांडी जिलों की महिलाएं मेहमानों के लिए सम्मान और स्नेह के प्रतीक के रूप में कढ़ाई शॉल बनाती हैं।

iii.कालाजीरा चावल: कोरापुट जिले में आदिवासी किसानों द्वारा उगाया जाता है, इसमें स्मृति सुधार, मधुमेह नियंत्रण और हीमोग्लोबिन के स्तर में वृद्धि जैसे औषधीय गुण होते हैं।

iv.काई चटनी: मयूरभंज जिले के आदिवासियों द्वारा खाई जाने वाली यह चटनी लाल बुनकर चींटियों से बनाई जाती है।

- यह प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर और 18 अमीनो एसिड से भरपूर है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है।

v.कांतेइमुंडी बैंगन: नयागढ़ जिले के बदाबनापुर और रत्नपुर क्षेत्रों में उत्पन्न; ये अपने अनोखे स्वाद, बीज और कांटेदार कांटों के लिए जाने जाते हैं।

vi.खजूर गुड़ 'खजूरी गुड़ा': इसकी उत्पत्ति गजपति जिले में हुई, यह खजूर के पेड़ों से प्राप्त एक प्राकृतिक स्वीटनर है।

vii.मगजी: यह ढेंकनाल जिले की एक मीठी वस्तु है जो भैंस के दूध के पनीर से बनाई जाती है।

GI टैग से सम्मानित उत्पादों की सूची

राज्य	GI उत्पाद	सामान
पश्चिम बंगाल	तांगेल साड़ियाँ	कपड़ा
	कोरियाल साड़ियाँ	
	गराड सिल्क साड़ियाँ	
ओडिशा	लांजिया सौरा की चित्रकारी (IDITAL)	हस्तशिल्प
	डुंगरिया कोंध कढ़ाई शॉल	कपड़ा
	ढेंकनाल मगजी	खाद्य सामग्री
	मयूरभंज काई चटनी	
	नयागढ़ कांतेइमुंडी बैंगन	कृषि
	गजपति खजूर गुड़ (खजुड़ी गुड़ा)	
	कोरापुट कालाजीरा चावल	

GI टैग के बारे में:

i.GI उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल (जैसे, एक शहर, क्षेत्र या देश) से मेल खाता है।

ii.औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन (अनुच्छेद 1 (2) और 10) और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू (TRIPS) समझौते (अनुच्छेद 22 से 24) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते भौगोलिक संकेतों को मान्यता देते हैं और नियंत्रित करते हैं।

iii.विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य भारत ने 15 सितंबर, 2003 से सामान का GI (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को अधिनियमित किया, और इसका उद्देश्य भौगोलिक संकेतों को पंजीकृत करना और उनकी सुरक्षा करना, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों की विरासत और विशिष्टता को संरक्षित करना है।

- **नोट:** दार्जिलिंग चाय वर्ष 2004 में GI टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था, दार्जिलिंग चाय के लिए GI टैग 26 अक्टूबर, 2033 तक वैध है।

<u>हाल के संबंधित समाचार:</u>

i.अरुणाचल प्रदेश ने 3 विशिष्ट उत्पादों: खामती चावल, तवांग से याक चुरपी, और तांगसा कपड़ा के लिए GI टैग प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

ii.तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से उत्पन्न होने वाले एक विशिष्ट प्रकार के ताड़ के जग्गेरी या "गुड़" उदंगुड़ी पनांगकरुपट्टी को GI टैग प्राप्त हुआ।

<u>ओडिशा के बारे में:</u>

मुख्यमंत्री– नवीन पटनायक

राज्यपाल– रघुबर दास

स्टेडियम- DRIEMS ग्राउंड, कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम

IMAC को 3 वर्षों में राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता में अपग्रेड किया जाएगा

हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय नौसेना **(IN)** के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र **(IMAC)** को लगभग 3 वर्षों में राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता **(NMDA)** केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। NMDA का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र **(IOR)** में समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है।

i.NMDA केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG), रक्षा मंत्रालय **(MoD)**; बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPS&W) सहित सात मंत्रालयों में फैले 15 विभागों और संगठनों को एकजुट करेगा।

ii.भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड **(BEL)**, रक्षा मंत्रालय **(MoD)** के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाई **(PSU)** को NMDA के लिए आवश्यक सभी आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंP गई है।

IMAC के बारे में:

i.IMAC नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम **(NC3I)** का नोडल सेंटर है।

ii.IMAC को 2012 में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था और 450 करोड़ रुपये की लागत से 2014 में चालू हो गया।

DoT ने सभी संस्थाओं के लिए M2M, WPAN/WLAN पंजीकरण अनिवार्य कर दिया

संचार मंत्रालय (MoC) के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने इन व्यवसायों में लगी सभी संस्थाओं के लिए मशीन-टू-मशीन (M2M) और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क/वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क (WPAN/WLAN) पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।

- सरलसंचार पोर्टल (saralsanchar.gov.in) के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया 31 मार्च, 2024 तक पूरी होनी चाहिए।
- इस अधिदेश के पीछे का कारण मानक-आधारित और सुरक्षित M2M/IoT इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण के दायरे को व्यापक बनाना है।

प्रमुख बिंदु:

i.सभी संस्थाओं में कंपनियां, सरकारी विभाग, संगठन, भागीदारी, LLP (सीमित देयता भागीदारी), संस्थान, उपक्रम, स्वामित्व फर्म, समाज, M2M सेवा प्रावधान और WPAN/WLAN कनेक्टिविटी प्रावधान में लगे ट्रस्ट शामिल हैं।

ii.गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अधिकृत दूरसंचार लाइसेंसधारियों से दूरसंचार संसाधनों को वापस लिया जा सकता है या वियोग किया जा सकता है।

iii.यह अधिदेश दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP), KYC (नो योर कस्टमर), सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन और अन्य के साथ इंटरफेस से संबंधित M2M सेवा प्रदाताओं और WPAN/WLAN कनेक्टिविटी प्रदाताओं की चिंताओं का समाधान करेगा।

iv.उपरोक्त अधिदेश ने M2M संचार में स्पेक्ट्रम, रोमिंग और सेवा की गुणवत्ता (QoS) संबंधी आवश्यकताओं पर TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) की सिफारिशों का भी पालन किया।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के बारे में:

स्थापना- 1997

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली

MoHFW ने गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची M के तहत संशोधित फार्मा विनिर्माण नियमों को अधिसूचित किया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (**MoHFW**) ने फार्मा और बायोफार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स के लिए मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भारत के राजपत्र में ड्रग्स एंड कास्मेटिक रूल्स, 1945 की **अनुसूची M** दिशानिर्देशों के तहत **संशोधित फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स** को अधिसूचित किया।

- अनुसूची M फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स के लिए **गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP)** निर्धारित करती है। संशोधित अनुसूची M भारत में GMP को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत करेगी।
- संशोधित अनुसूची M को 'गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) और फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स के लिए परिसर, संयंत्र और उपकरण की आवश्यकताओं' को सुनिश्चित करने के लिए नियमों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

नोट: ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 का अनुसूची M भाग भारत में फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स द्वारा अपनाए जाने वाले 'GMP' से संबंधित है।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य ड्रग्स के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और मैन्युफैक्चर और बेची जाने वाली ड्रग्स की गुणवत्ता में विश्वास पैदा करना है।

संशोधित अनुसूची M:

i.ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) के साथ परामर्श के बाद, केंद्र सरकार ने ड्रग्स (अमेंडमेंट) रूल्स, 2023 के तहत संशोधित रूल्स को अधिसूचित किया।

ii.संशोधित अनुसूची M में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए निम्नलिखित शामिल हैं:

- फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम (PQS) का परिचय;
- एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (API) का पुनः परीक्षण;
- एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यु (PQR);
- क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट (QRM);
- गाइडलाइन्स फॉर इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एंड वेलिडेशन;
- ए कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज सिस्टम फॉर ऑल ड्रग प्रोडक्ट्स

iii.संशोधित अनुसूची M में 13 भाग हैं जो फार्मास्युटिकल दवाओं के निर्माण के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए GMP दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।
iv.संशोधित दिशानिर्देशों में पानी और हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर-कंडीशनिंग (HVAC) सिस्टम्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता की आवश्यकता है।
v.संशोधित नियम कंपनी के टर्नओवर के आधार पर लागू किए जाएंगे:

- 250 करोड़ रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले मध्यम और छोटे निर्माताओं को प्रकाशन की तारीख से 12 महीने के भीतर संशोधित नियमों को लागू करना होगा;
- 250 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले बड़े निर्माताओं को परिवर्तनों को लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा।

नई श्रेणियाँ:

संशोधित नियमों में खतरनाक पदार्थों वाले फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स सहित दवाओं की 5 नई श्रेणियां शामिल की गई हैं:

- सेक्स हार्मोन; स्टेरॉयड (एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक); साइटोटोक्सिक सब्स्टांसेस; बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स; मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए रेडियोफार्मास्यूटिकल्स, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और इन्वेस्टिगेशनल फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट।

GMP:

GMP अनिवार्य मानक हैं जो सामग्री, विधियों, मशीनों, प्रक्रियाओं, कर्मियों और सुविधा/पर्यावरण को नियंत्रित करके प्रोडक्ट्स का निर्माण और गुणवत्ता लाते हैं।
इसे पहली बार 1988 में ड्रग्स एंड कास्मेटिक रूल्स, 1945 की अनुसूची M के तहत शामिल किया गया था और अंतिम संशोधन जून 2005 में किया गया था।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.भारत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दवाओं का एक प्रमुख निर्यातक है, जिन्हें WHO-GMP प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।
ii.2 अगस्त, 2023 को, MoHFW ने WHO-GMP प्रमाणन प्राप्त करने के लिए छोटे निर्माताओं के लिए 6 महीने और बड़ी इकाइयों के लिए 12 महीने की समय सीमा निर्धारित की।

NH66 पर भारत के पहले नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन का अनावरण किया गया

डॉ. V.K. सारस्वत, सदस्य (S&T), NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) ने मुंबई-गोवा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे (NH) -66 पर भारत के पहले नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन का उद्घाटन किया। यह फोर लेन रोड NH-66 के इंदापुर-पनवेल सेक्शन पर लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है।

- रोड का निर्माण नई दिल्ली स्थित कॉउंसिल ऑफ साइंटिफिक & इंडस्ट्रियल रिसर्च (**CSIR**) - सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट (**CRRI**) के मार्गदर्शन में मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित JSW स्टील द्वारा किया गया था।
- यह परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ स्टील (**MoS**) द्वारा प्रायोजित थी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (**NHAI**) द्वारा समर्थित थी।
- इस रोड के निर्माण के लिए लगभग 80,000 टन CONARC स्टील स्लैग को JSW स्टील डोल्वी, रायगढ़ प्लांट में संसाधित स्टील स्लैग समुच्चय के रूप में परिवर्तित किया गया था।

DGCA ने पायलटों की थकान को कम करने & विमान सुरक्षा बढ़ाने के लिए विमान का चालक दल के लिए नए विमान कर्तव्य समय नियमों में संशोधन किया

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों और चालक दल के बीच थकान को दूर करने और समग्र विमान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपने **विमान कर्तव्य समय सीमाओं (FDTL) विनियमों** में पर्याप्त संशोधन पेश किए हैं।

- संशोधित FDTL विनियमों में आराम की अवधि में वृद्धि, रात्रि कर्तव्य को फिर से परिभाषित करना और एयरलाइंस द्वारा साझा की जाने वाली नियमित थकान रिपोर्ट शामिल हैं।
- विमान चालक दल के लिए FDTL नियमों में लागू किए गए महत्वपूर्ण बदलाव विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।

समयरेखा: संशोधित FDTL नियम तुरंत प्रभावी हैं, और 1 जून, 2024 तक अनुपालन अनिवार्य है।

संशोधित विनियम:

i.DGCA ने विमान चालक दल के लिए अनिवार्य साप्ताहिक आराम अवधि को पिछले 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है।

ii.DGCA ने रात में (12 AM से 6 AM के बीच) काम करने वाले पायलटों के लिए अधिकतम विमान कर्तव्य अवधि को 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया।

- इसने इस अवधि के दौरान रात के संचालन के दौरान विमान उतरना की संख्या को 6 से घटाकर 2 तक सीमित कर दिया।

iii.रात की परिभाषा को भी समायोजित किया गया है, जो पहले 12 AM से 5 AM की तुलना में अब 12 AM से 6 AM तक फैली हुई है।

- सुबह के दौरान 1 घंटे का यह समायोजन पर्याप्त आराम की सुविधा प्रदान करेगा और रात की ड्यूटी अवधि को विशेष रूप से 0200-0600 घंटे तक विंडो ऑफ़ सर्कैडियन लो (WOCL) के भीतर सिंक्रनाइज़ करेगा।

iv.संशोधित नियमों में समय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संचालन को भी ध्यान में रखा गया है।

- अधिकतम विमान समय: रात में विमान संचालन के दौरान 8 घंटे तक सीमित।
- अधिकतम विमान कर्तव्य अवधि: रात के संचालन के लिए 10 घंटे तक सीमित।

v.DGCA का आदेश है कि सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को गहन विश्लेषण के बाद त्रैमासिक थकान रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें ऐसी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई भी शामिल है।

- इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि थकान रिपोर्ट गैर-दंडात्मक और गोपनीयता नीति का पालन करेगी।

vi.DGCA ने 14 घंटे से अधिक की विमानों के लिए अधिकतम विमान समय को 17 घंटे तक सीमित कर दिया है और एयरलाइंस को प्रत्येक विमान के बाद 120 घंटे की न्यूनतम आराम अवधि प्रदान करने के लिए बाध्य किया है।

- लगातार 2 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज (ULR) विमानों के बाद, अनिवार्य आराम अवधि 24 घंटे बढ़ जाती है।

थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली (FRMS):

इसके अलावा, DGCA जल्द ही थकान प्रबंधन की एक नई व्यवस्था यानी थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली (FRMS) को अपनाने की दिशा में बदलाव करेगा, जो विमान चालक दल की थकान की निगरानी बढ़ाने के लिए एक डेटा-संचालित दृष्टिकोण होगा।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के बारे में:

DGCA नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।

महानिदेशक– विक्रम देव दत्त

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली

हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स भारत की पहली BSI प्रमाणित ISO 27001:2022 पेट्रोकेमिकल फर्म बन गई

हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड **(HPL)** भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन **(ISO)** / अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन **(IEC) 27001:2022** प्रमाणित पेट्रोकेमिकल संगठन बन गया है।

- यह प्रमाणन यूनाइटेड किंगडम **(UK)** स्थित प्रमाणन निकाय, ब्रिटिश मानक संस्थान **(BSI)** द्वारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल **(WB)** में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु:

i.प्रमाणन आंतरिक और बाहरी हितधारकों के बीच सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल वातावरण के प्रति HPL की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।
ii.इस प्रमाणीकरण ने संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करने और मूल्यवान डेटा और प्रणालियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया।
iii.डिजिटल रूप से परिवर्तित HPL कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अत्याधुनिक उपकरणों के साथ सशक्त बनाता है, जिससे टीम वर्क और एक डिजिटल संस्कृति बढ़ती है जो रचनात्मकता और दक्षता को प्रोत्साहित करती है।

ISO/IES 27001:2022 के बारे में

i.ISO/IEC 27001:2022 अक्टूबर 2022 में प्रकाशित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) कार्यक्रम का नवीनतम संस्करण है।

- इसे शुरुआत में फरवरी 2022 में **"अभ्यास संहिता"** के रूप में प्रकाशित किया गया था।

ii.यह महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा और सूचना संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
iii.यह व्यवसाय प्रथाओं के डिजिटलीकरण और संबंधित खतरों के साथ एक संगठन की सूचना सुरक्षा स्थिति को भी संरेखित करता है।

ब्रिटिश मानक संस्थान (BSI) के बारे में:

BSI दुनिया का पहला मानक निकाय और ISO का संस्थापक सदस्य है।
मुख्य कार्यकारी– सुसान टेलर मार्टिन
संस्थापक - सर जॉन वोल्फ-बैरी
स्थापना – 1901

हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (HPL) के बारे में:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) – नवनीत नारायण
मुख्यालय – कोलकाता, पश्चिम बंगाल (WB)
स्थापना – 1985

इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150वां स्थापना दिवस - 15 जनवरी 2024

15 जनवरी, 2024 को, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट **(IMD)** ने राष्ट्र के लिए अपनी स्थापना और सेवा के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपना **150 वां स्थापना दिवस** मनाया।
IMD की स्थापना के 150वें वर्ष का उद्घाटन समारोह विज्ञान भवन, नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित किया गया था।
प्रमुख लोग: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, MoES सम्मानित अतिथि थे। इस आयोजन में पूरे भारत से लगभग 1,200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पृष्ठभूमि:

i.IMD की स्थापना 1875 में भारत सरकार के पहले वैज्ञानिक विभागों में से एक के रूप में की गई थी।

ii.150 वर्षों की सेवा के उपलक्ष्य में, IMD ने 15 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2025 तक एक वर्ष के दौरान पूरे भारत में अपने सभी उप-कार्यालयों में इस कार्यक्रम को मनाने का प्रस्ताव दिया है।

कार्यक्रम की मुख्य बातें:

i.कार्यक्रम के दौरान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने **IMD का थीम सॉन्ग** जारी किया, जिसमें **"सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय"** यानी "कमिटमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल" के सिद्धांत के तहत भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इसके विकास और प्रदान की गई सेवाओं पर प्रकाश डाला गया।

- उन्होंने 1875 से IMD और इसकी सेवाओं के विकास पर **स्मारिका** भी लॉन्च की।

ii.VP ने निम्नलिखित भी जारी और लॉन्च किया,

स्वदेशी रूप से विकसित डिसिशन सपोर्ट सिस्टम- WAFES:

IMD ने एक इन-हाउस वेब-जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम (GIS) आधारित इंटीग्रेटेड डिसिशन सपोर्ट सिस्टम (**DSS**) विकसित की है, जिसे वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्ट इनेबलिंग सिस्टम (**WAFES**) कहा जाता है, जो पंच महाभूत यानी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से प्रेरित है।

WAFES के बारे में:

i.यह एक विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफ़ॉर्म है, जो गंभीर वेदर की घटनाओं और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के लिए निर्णय लेने में सहायता करता है।

ii.इस सिस्टम में मेट्रोलॉजिकल इनफार्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम (MICS), डेटा इनफार्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (DIPS), सिंथेसाइज्ड इंटीग्रेटेड विज़ुअलाइज़ेशन सिस्टम (SIVS), और पब्लिक वेदर इनफार्मेशन सिस्टम (PWIS) जैसे मॉड्यूल शामिल हैं।

iii.यह "**UPHHEATT**" पहल के तहत शहरी, बिजली, जल विज्ञान, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।

किसानों के लिए पंचायत मौसम सेवा पोर्टल:

पंचायत मौसम सेवा पोर्टल (https://mausam.imd.gov.in/greenalerts) संयुक्त रूप से IMD, MoES, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) और ग्रीन अलर्ट मौसम सेवा द्वारा विकसित किया गया था।

यह पोर्टल प्रत्येक पंचायत प्रमुख और सचिव को अंग्रेजी, हिंदी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में वेदर फोरकास्ट प्रदान करता है।

- यह किसानों को कृषि गतिविधियों की योजना बनाने, इनपुट कॉस्ट्स को कम करने, फसल के नुकसान को कम करने और उत्पादन और आय को बढ़ाने में सहायता करता है।

IMD का मोबाइल ऐप और मौसम ग्राम:

IMD ने एक इंटीग्रेटेड GIS आधारित मोबाइल ऐप **MAUSAM** लॉन्च किया और कार्यक्रम के दौरान "सबका साथ सबका विकास" कार्यक्रम के अनुरूप मौसम ग्राम जारी किया।

- मौसम ग्राम मोबाइल ऐप "मौसम" के माध्यम से उपलब्ध है।

मौसम ऐप के बारे में:

i.यह 12 भारतीय भाषाओं में वेदर सर्विसेज प्रदान करता है, जिसमें वर्तमान वेदर, प्रति घंटे से लेकर 7 दिन के फोरकास्ट और विभिन्न सलाह शामिल हैं।

ii.यह उपयोगकर्ताओं को मानचित्र या खोज फ़ंक्शन के माध्यम से उनके स्थान के लिए ऑब्सेर्वशन्स, फोरकास्ट और वॉर्निंग्स देखने की अनुमति देता है।

iii.फोरकास्ट अगले 10 दिनों तक प्रति घंटे, 3 घंटे और 6 घंटे के आधार पर उपलब्ध हैं।

नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज (NFCS)

IMD ने क्लाइमेट खतरों और चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए **नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज (NFCS)** लॉन्च किया।

उद्देश्य: कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए विज्ञान-आधारित क्लाइमेट निगरानी और भविष्यवाणी सेवाओं के उत्पादन और वितरण को मजबूत करना।

प्रमुख बिंदु:

i.IMD भारत में 90% से अधिक आबादी को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

ii.IMD दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और कई अन्य विदेशी देशों को वेदर फोरकास्ट सर्विसेज भी प्रदान करता है।

iii.IMD वर्षा, तापमान, हवा & दबाव और क्लाइमेट चरम सीमा जैसे बुनियादी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स की क्लाइमेटोलॉजी तैयार करता है। इसे हर 10 साल में एक बार अपडेट किया जाता है।

iv.2021 से, IMD गतिशील मल्टी मॉडल पहनावा क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम के आधार पर प्रत्येक महीने और मौसम के लिए क्लाइमेट फोरकास्ट प्रदान करता है।

v.IMD भारत सरकार की 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली (**LiFE**)' योजना के अनुरूप, घाटे को कम करने और अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बिजली & नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को भी सर्विसेज प्रदान कर रहा है।

हाल के संबंधित समाचार:

i.पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने परंपरा और संरक्षण में निहित स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और 'LiFE' - 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली' आंदोलन के विचारों को बढ़ावा देने के लिए 2 नई पहल, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) और इकोमार्क योजना शुरू की।

ii.16 अक्टूबर, 2023 को, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री राज कुमार (RK) सिंह ने नई दिल्ली, दिल्ली से एक नया इलेक्ट्रिक वाहन (EV) -रेडी इंडिया डैशबोर्ड (evreadyindia.org) लॉन्च किया।

इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के बारे में:

मेट्रोलॉजी के महानिदेशक– डॉ. मृत्युंजय महापात्र,

मुख्यालय– दिल्ली

स्थापना- 1875

2022-23 में बागवानी उत्पादन 2.32% बढ़कर 355.25 मिलियन टन होने का अनुमान है

18 जनवरी, 2024 को **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** (MoA&FW) ने 2022-23 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया।

- इसके अनुसार, 2022-23 के लिए कुल बागवानी उत्पादन का अनुमान **355.25 मिलियन टन** है, जो 2021-22 (अंतिम) की तुलना में लगभग 8.07 मिलियन टन अधिक (2.32% की वृद्धि) है।
- बागवानी का कुल क्षेत्रफल भी 2022-23 (तीसरे अग्रिम अनुमान) में मामूली रूप से बढ़कर **28.34 मिलियन हेक्टेयर** हो गया, जो 2021-22 (अंतिम) अनुमान में 28.04 मिलियन हेक्टेयर था।

मुख्य विशेषताएं:

i.2022-23 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फलों, सब्जियों, वृक्षारोपण फसलों, मसालों, फूलों और शहद का उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान है।

ii.फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन (2021-22) से बढ़कर 109.53 मिलियन टन (2022-23) होने का अनुमान है।

ii.सब्जी उत्पादन 209.14 मिलियन टन (2021-22) से बढ़कर 213.88 मिलियन टन (2022-23) होने का अनुमान है।

iii.बागान फसलें 15.76 मिलियन टन (2021-22) से बढ़कर 16.84 मिलियन टन (2022-23) होने की उम्मीद है, जो 6.80% की वृद्धि दर्शाता है।

iv.आलू का उत्पादन 2021-22 में 56.18 मिलियन टन से बढ़कर 60.22 मिलियन टन तक पहुंचने के लिए तैयार है।

v.टमाटर का उत्पादन 2022-23 में 20.37 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 में 20.69 मिलियन टन से थोड़ा कम है।

vi.प्याज का उत्पादन FY23 में 4.7% घटकर 30.2 मिलियन टन होने का अनुमान है।

- अनियमित वर्षा और सिंचाई प्रभावित होने वाले जलाशयों के स्तर में कमी के कारण प्रमुख महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्रों में रबी प्याज की बुआई में 20% तक की कमी आई है।
- 2023-24 के लिए अनुमानित ख़रीफ़ और देर से ख़रीफ़ प्याज का उत्पादन 30.5 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष के 41.7 मिलियन टन के अनुमान से कम है।

MeitY सचिव ने केरल में भारत का पहला ग्राफीन सेंटर, IIoT CoE लॉन्च किया

दो प्रमुख कार्यक्रम अर्थात् "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (**CoE**) इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स (**IIoT**) सेंसर्स" और भारत का पहला ग्राफीन सेंटर "इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन (**IICG**)" कोच्चि, केरल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (**MeitY**) के सचिव S कृष्णन द्वारा लॉन्च किए गए थे।

इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन (IICG) के बारे में:

i.IICG का लक्ष्य ग्राफीन और द्वि-आयामी (2D) सामग्री प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान & विकास **(R&D)**, उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।

ii.IICG को विभिन्न उद्योगों के सहयोग से MeitY, भारत सरकार (GoI), केरल राज्य सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

iii.IICG को सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (C-MET), डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल (DUK) (जिसे पहले इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट-केरला (IIITM-K) के नाम से जाना जाता था) और टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

CoE इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IIoT):

i.CoE का लक्ष्य C-MET और DUK में पूरक सेंसर अनुसंधान, विकास और अनुप्रयोग विशेषज्ञता को एक साथ लाना है।

ii. CoE के एप्लिकेशन डोमेन को उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जिसमें मेकर विलेज (केरल में) और केरल स्टार्टअप मिशन इकोसिस्टम में स्टार्ट-अप शामिल हैं।

iii.IIOT की स्थापना MeitY, GoI और केरल राज्य सरकार द्वारा की गई है।

अतिरिक्त जानकारी:

i.मेकर विलेज का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम, **हार्डटेक 2024**, केरल में भी लॉन्च किया गया था।

ii.यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में उद्योगों, स्टार्टअप्स, निवेशकों, शिक्षाविदों, R&D संगठनों के नेताओं को एक साथ लाएगा।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) के बारे में:

केंद्रीय मंत्री - अश्विनी वैष्णव (राज्यसभा - ओडिशा)

राज्य मंत्री (MoS) – राजीव चन्द्रशेखर (राज्यसभा कर्नाटक)

गोवा पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया

गोवा सरकार ने पर्यावरण बहाली, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर पर्यटन को फिर से परिभाषित करने के लिए भारत का पहला **पुनर्योजी पर्यटन मॉडल** लॉन्च किया है।

- इस मॉडल का लक्ष्य **एकादश तीर्थ** अभियान के तहत 11 आध्यात्मिक स्थलों को बढ़ावा देना है।
- अभियान में स्थानीय समुदायों को उनकी संस्कृति, भोजन और जीवन शैली की खोज, समझ और प्रक्षेपण में शामिल किया गया है।

- यह मॉडल गोवा की मुक्ति की 62वीं वर्षगांठ (19 दिसंबर, 2023) को चिह्नित करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- मॉडल का लॉन्च विश्व पर्यटन के मनीला घोषणा (1980) और समूह-20 (**G20**) पर्यटन मंत्रियों के कार्य समूह की बैठक के सिद्धांतों के अनुरूप है जो जून 2023 में गोवा में आयोजित किया गया था।

GoI ने 'अनुवादिनी' ऐप का उपयोग करके 22 भाषाओं में शैक्षिक अध्ययन सामग्री बनाने की योजना बनाई

भारत सरकार **(GoI)** का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस **(AI)**-आधारित **'अनुवादिनी'** मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भारतीय संविधान की **8वीं** अनुसूची में सूचीबद्ध सभी **22** भाषाओं में **स्कूल** और **उच्च शिक्षा** के तहत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना है।

प्रमुख बिंदु:

i.इस उद्देश्य के लिए, शिक्षा मंत्रालय **(MoE)** ने शैक्षिक नियामकों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रमुखों को अगले तीन वर्षों के भीतर **(2027 तक)** ऐसी अध्ययन सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया है।

ii.राज्य के स्कूलों और विश्वविद्यालयों से संबंधित मुद्दे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **(UGC)**, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद **(AICTE)**, और शिक्षा मंत्रालय **(MoE)** के तहत स्कूल शिक्षा & साक्षरता विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

iii.यह पहल हर स्तर पर शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति **(NEP)**-2020 के अनुरूप है।

अनुवादिनी के बारे में:

i.अनुवादिनी एक आवाज & दस्तावेज़ AI अनुवाद उपकरण है।

ii.यह **22 क्षेत्रीय भारतीय** & **विदेशी भाषाओं** का समर्थन करता है जिससे भाषा संबंधी बाधाएं कम हो जाती हैं।

iii.इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, स्नातक, स्नातकोत्तर और कौशल पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए अनुवादिनी ऐप पिछले दो वर्षों से उपयोग में है।

iv.ये किताबें इलेक्ट्रॉनिक - नॉलेज अनलीशेड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेज **(ई-कुंभ)** पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

v.पोर्टल ने स्कूली पुस्तकों (30 भाषाओं) और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री (13 भाषाओं) का भी अनुवाद किया।

भारत का 75वाँ गणतंत्र दिवस- 26 जनवरी, 2024

भारत ने 26 जनवरी 2024 को अपना 75वां गणतंत्र दिवस (R-दिवस) मनाया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम और परेड नई दिल्ली, दिल्ली में नव-पुनर्निर्मित और नामित कर्तव्य पथ (जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था) पर आयोजित किया गया था। भारत का गणतंत्र दिवस उस तारीख को चिह्नित करता है और जश्न मनाता है जिस दिन 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था।

- **भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने** मेजर सौम्या शुक्ला ASC के साथ **भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया**, इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और स्वदेशी 105-mm इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई।

R-दिवस 2024 की थीम:

'विकसित भारत' (डेवलप्ड इंडिया) और **'भारत- लोकतंत्र की मातृका'** (भारत - द मदर ऑफ डेमोक्रेसी)

75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि:

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे। यह 6 वीं बार है कि फ्रांसीसी नेता ने 1976 और 1998 में राष्ट्रपति जैक्स शिराक के बाद इस अवसर पर भाग लिया, उसके बाद 1980 में वालेरी गिस्कार्ड d'एस्टिंग, 2008 में निकोलस सरकोजी और 2016 में फ्रेंकोइस ओलांद ने इस अवसर पर भाग लिया।

- यह 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल दिवस पर भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के बाद एक पारस्परिक आदान-प्रदान का भी प्रतीक है।

- फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ समारोह में समाप्त होगी।

पुरस्कार के संबंध में मुख्य विशेषताएं:

सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में शामिल हैं,

i.परम वीर चक्र विजेता - सूबेदार मेजर (मानद कैप्टन) योगेन्द्र सिंह यादव (सेवानिवृत्त) और सूबेदार मेजर संजय कुमार (सेवानिवृत्त)

ii.अशोक चक्र विजेता - मेजर जनरल CA पीठावाला (सेवानिवृत्त), कर्नल D. श्रीराम कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल जस राम सिंह (सेवानिवृत्त)।

राष्ट्रपति ने छह भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक पदक को मंजूरी दी

भारत के राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट वीरता, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण, विशिष्ट/सराहनीय सेवा के लिए 6 उत्कृष्ट भारतीय तटरक्षक (ICG) कर्मियों को तटरक्षक पदकों को मंजूरी दी। इसमें एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और 5 तटरक्षक पदक शामिल हैं।

- 26 जनवरी, 1990 से, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखने में उनकी उत्कृष्टता, साहस और प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ICG कर्मियों को प्रदान किए जाते हैं।

पुरस्कार	प्राप्तकर्ता
राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा)	महानिरीक्षक (IG) भीष्म शर्मा, TM(0247-L)
तटरक्षक पदक (वीरता)	Comdt (कमांडेंट) सुनील दत्त (0662-D) Comdt (JG) सौरभ (0735-S)
तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा)	उप महानिरीक्षक (DIG) अनिल कुमार परायिल (0265-C) DIG जमाल ताहा (4085-J) दीपक रॉय, P/Adh (AR), 01111-Z

आधिकारिक सूची के लिए यहां क्लिक करें

राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार-2023 प्रदान करने को मंजूरी दी

राष्ट्रपति ने 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार-2023 प्रदान करने की मंजूरी दी, जिसमें 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 जीवन रक्षा पदक शामिल हैं। तीन पुरस्कार विजेता मरणोपरांत हैं।

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक पुरस्कार विजेता
मास्टर एंथोनी वनमाविया (मरणोपरांत), मिजोरम सुश्री मेलोडी लालरेमरूती (मरणोपरांत), मिजोरम श्री सूरज R (मरणोपरांत), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार-2023 की पूरी आधिकारिक सूची के लिए यहां क्लिक करें

जीवन रक्षा पदक के बारे में:

1961 में स्थापित, जीवन रक्षा पदक, पानी में डूबने, दुर्घटनाओं, आग की घटनाओं, बिजली के झटके, प्राकृतिक आपदाओं, खानों में बचाव अभियान आदि जैसे मामलों में किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में मानव स्वभाव के

सराहनीय कार्यों के लिए व्यक्तियों को मान्यता देता है। तीन श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया है, प्रत्येक पुरस्कार में एक पदक, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक मौद्रिक भत्ता शामिल होता है।

i.सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक - बचावकर्ता के जीवन के लिए बहुत बड़े खतरे की परिस्थितियों में जीवन बचाने में विशिष्ट साहस के लिए।

- मौद्रिक भत्ता- **2 लाख रुपये**

ii.उत्तम जीवन रक्षा पदक - बचावकर्ता के जीवन के लिए बड़े खतरे की परिस्थितियों में जीवन बचाने में साहस और तत्परता के लिए।

- मौद्रिक भत्ता- **1.5 लाख रुपये**

iii.जीवन रक्षा पदक - बचावकर्ता को गंभीर शारीरिक चोट की परिस्थितियों में जीवन बचाने में साहस और तत्परता के लिए।

- मौद्रिक भत्ता- **1 लाख रुपये**

यह अलंकरण राज्य/UT (केंद्र शासित प्रदेश) सरकार या संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे पुरस्कार विजेता संबंधित होता है।

राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों के लिए 1132 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी:

आयोजन के दौरान, पुलिस, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा & सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मियों को वीरता/सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार ने 16 वीरता/सेवा पदकों को चार पदकों में समेकित करके पुरस्कार प्रणाली को सुव्यवस्थित और बदल दिया है। ये वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक (PMG); वीरता पदक (GM); विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (PSM), और सराहनीय सेवा पदक (MSM) हैं।

26 जनवरी, 2024 के दौरान दिए गए पदकों का विवरण

पदकों के नाम	प्रदान किये गये पदकों की संख्या
वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक (PMG)	02
वीरता पदक (GM)	275
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (PSM)	102
सराहनीय सेवा पदक (MSM)	753

पुरस्कारों के बारे में:

i.PMG और GM को जीवन और संपत्ति को बचाने में, या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में क्रमशः वीरता के दुर्लभ विशिष्ट अधिनियम और वीरता के विशिष्ट कार्य के आधार पर सम्मानित किया जाता है, संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों के संबंध में जोखिम का अनुमान लगाया जा रहा है।

ii.PSM को सेवा में विशेष प्रतिष्ठित रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया जाता है और MSM को संसाधन और कर्तव्य के प्रति समर्पण जैसी मूल्यवान सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

i.PMG को **2 BSF** (सीमा सुरक्षा बल) कर्मियों अर्थात् **स्वर्गीय सनवाला राम विश्नोई** & **स्वर्गीय शिशु पाल सिंह** को उनके उत्कृष्ट शांति कार्य के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (MONUSCO) में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के हिस्से के रूप में उनके उत्कृष्ट शांति कार्य के लिए बुटेम्बो में मोरक्कन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन (MORRDB) कैंप में BSF के 15वें कांगो दल के सदस्यों के रूप में सम्मानित किया गया है।

- आधिकारिक सूची के लिए यहां क्लिक करें

ii.277 वीरता पुरस्कारों में, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 119 कर्मी; जम्मू & कश्मीर क्षेत्र से 133 कर्मी और अन्य क्षेत्रों से 25 कर्मी है।

- आधिकारिक सूची के लिए यहां क्लिक करें

iii.102 PSM में से 94 पुलिस सेवा को, 4 अग्निशमन सेवा को, और 4 नागरिक सुरक्षा & होम गार्ड सेवा को दिए गए।

- आधिकारिक सूची के लिए यहां क्लिक करें

iv.753 MSM में से 667 पुलिस सेवा को, 32 अग्निशमन सेवा को, 27 नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड सेवा को और 27 सुधार सेवा को दिए गए।

- आधिकारिक सूची के लिए यहां क्लिक करें
- विशेष रूप से, MSM को महाराष्ट्र कैडर के 2005-बैच के IPS (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी **मनोज कुमार शर्मा** को भी प्रदान किया जाता है, जिनके जीवन ने हिंदी फिल्म 12वीं फेल को प्रेरित किया। वह पुरस्कार पाने वाले 37 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) कर्मियों में से एक थे।

v.पदक प्राप्तकर्ताओं की राज्यवार/बलवार सूची

R-दिवस समारोह की मुख्य विशेषताएं

सरकार ने 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया

75वें गणतंत्र दिवस समारोह को चिह्नित करने के लिए, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय ने **75 रुपये** का स्मारक चांदी का सिक्का और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का एक डाक टिकट जारी किया। इसकी ढलाई **भारत सरकार टकसाल**, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा की जाती है।

- यह 75 रुपये मूल्यवर्ग में है और इसका वजन 40 ग्राम है।
- सिक्के का व्यास 44 मिलीमीटर है और इसमें 200 दाँतेदार दाँत हैं।
- सिक्के के केंद्र में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष और नीचे 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है।
- बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में 'भारत' है, और दाईं ओर अंग्रेजी में 'INDIA' है।

प्रमुख बिंदु:

i.स्मारक सिक्के वैध मुद्रा हैं लेकिन सामान्य उपयोग के लिए नहीं। इन्हें www.indiagovtmint.in जैसी निर्दिष्ट वेबसाइटों से प्राप्त किया जा सकता है। सिक्के का मूल्य छपे हुए सिक्के से अधिक है।

ii.वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 वर्षों के लिए **20 रुपये** और श्री कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी के लिए **100 रुपये** के बाद यह 2024 का **तीसरा स्मारक** सिक्का जारी है।

75वें R-दिवस परेड में नारी शक्ति केंद्र स्तर पर है

पहली बार, सभी महिलाओं की त्रि-सेवा टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया, जो भारत की बढ़ती 'नारी शक्ति' (वीमेन पावर) को दर्शाता है। एक और पहली बार, परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्ययंत्र जैसे शंख, नादस्वरम, नागदा आदि बजाते हुए की गई।

- भारतीय वायु सेना (IAF), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) अर्धसैनिक बलों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और अन्य संगठनों की झांकियों ने अपने-अपने अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को प्रदर्शित किया।

मुख्य विचार:

31 वर्षीय **मेजर दिव्या त्यागी** 2024 गणतंत्र दिवस परेड में **बॉम्बे सैपर्स** की पूर्ण पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना (IA) की पहली महिला अधिकारी बनीं। वह कोर ऑफ इंजीनियर की 115वीं इंजीनियर रेजिमेंट में एक अधिकारी हैं।

75वें R-दिवस पर फ्रांस के बैंड और मार्चिंग दस्ते का प्रदर्शन किया गया

i.परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) की कुल **25 झांकियों** ने हिस्सा लिया।

- राज्यों और UT की झाँकियाँ - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
- मंत्रालयों और संगठनों की झाँकियाँ - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र (CSIR), संस्कृति मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र (CSIR), बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत का चुनाव आयोग, और गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय।

ii.परेड में फ्रांसीसी सैन्य दल भी शामिल था जिसमें 95 सैनिक और 33 सदस्यीय फ्रांसीसी बैंड दल शामिल थे।

- फ्रांसीसी दल में राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट (MRTT) विमान भी शामिल थे।
- बैंड दल का नेतृत्व कैप्टन खोरदा ने किया और फ्रांसीसी सैन्य दल का नेतृत्व कैप्टन नोएल लुइस ने किया और इसमें फ्रांसीसी विदेशी सेना के कोर के छह भारतीय अधिकारी शामिल थे।

ISRO की झांकी चंद्रयान-3 की सफलता को प्रदर्शित करती है

ISRO के चंद्रयान-3 मिशन की सफल लॉन्चिंग को झांकी बनाया गया. झांकी का विषय "चंद्रयान 3 ए सागा इन द इंडियन स्पेस हिस्ट्री" था।

- झांकी में सूर्य का अध्ययन करने के लिए सफल आदित्य L-1 मिशन के साथ-साथ गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के मिशनों का चित्रण किया गया।

R-दिवस परेड में विभिन्न राज्यों की 1,900 साड़ियाँ प्रदर्शित की गईं

संस्कृति मंत्रालय ने परेड के दौरान एक कपड़ा संस्थापन 'अनंत सूत्र - द एंडलेस थ्रेड' प्रस्तुत किया। यह देश भर से लगभग 1,900 साड़ियों और पर्दों को लकड़ी के तख्ते पर प्रदर्शित करके कालातीत भारतीय साड़ियों को श्रद्धांजलि देता है।

- इसमें बुनाई और कढ़ाई के विवरण के लिए QR (क्विक रिस्पांस) कोड शामिल थे। इंस्टॉलेशन में 150 साल पुरानी साड़ी पर भी प्रकाश डाला गया है।

राष्ट्रपति ने राजसी घोड़ा-बग्गी के साथ 250 साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजसी घोड़ा-बग्गी के साथ 250 साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया। वह और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रॉन पारंपरिक बग्गी में कार्तव्य पथ पर पहुंचे, जिसने 40 साल बाद वापसी की।

- उनकी सुरक्षा प्रेसिडेंटस बॉडीगार्ड - "राष्ट्रपति के अंगरक्षक" द्वारा की गई। राष्ट्रपति का अंगरक्षक भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। विशेष रूप से, इस रेजिमेंट ने 1773 में अपनी स्थापना के बाद से 250 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

प्रमुख बिंदु:

i.सोने की परत चढ़ी हुई बग्गी, जो राष्ट्रीय प्रतीक से सुसज्जित है, भारतीय और ऑस्ट्रियाई घोड़ों के मिश्रण से खींची जाती है।

ii.राष्ट्रपति बग्गी का उपयोग 1984 तक गणतंत्र दिवस समारोहों के लिए किया जाता था, लेकिन तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसे बंद कर दिया गया था।

iii.बुग्गी का इस्तेमाल आखिरी बार ज्ञानी जैल सिंह ने 1984 में किया था।

iv.2014 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए इसका दोबारा इस्तेमाल किया।

- उनके उत्तराधिकारी राम नाथ कोविंद ने बग्गी की सवारी की परंपरा को जारी रखा। 2017 में शपथ लेने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति की बग्गी में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।

मुख्य नोट्स:

i.वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता और प्रोजेक्ट वीर गाथा का तीसरा संस्करण गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया।

ii.लाल किले पर 'भारत पर्व' 23-31 जनवरी, 2024 तक 'जनभागीदारी' थीम पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणतंत्र दिवस की झांकी, सैन्य बैंड, सांस्कृतिक प्रदर्शन, शिल्प बाजार और फूड कोर्ट का प्रदर्शन किया जाएगा।

iii.लाल किले में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पराक्रम दिवस 23 जनवरी, 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें 3-D प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइट & साउंड शो, नाटक और नृत्य प्रदर्शन जैसी गतिविधियां शामिल थीं।

नोट:

i.भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।

ii.26 जनवरी, 1950 को संविधान को अपनाने के साथ राष्ट्र ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया।

iii.भारत के संविधान ने भारत के शासकीय दस्तावेज़ के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित कर दिया, इस प्रकार देश को ब्रिटिश राज से अलग एक गणतंत्र में बदल दिया गया।

ONGC को ग्रीन एनर्जी सब्सिडियरी बनाने के लिए MoPNG की मंजूरी मिली

ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (**ONGC**) को ग्रीन एनर्जी और गैस व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी **स्थापित** करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस(**MoPNG**) से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी 5 दिसंबर 2023 को मिली थी।

- सब्सिडियरी का प्रस्तावित नाम **"ONGC ग्रीन लिमिटेड"** है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MoCA) की मंजूरी के अधीन है।

नोट: ONGC MoPNG के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) है।

ग्रीन एनर्जी सब्सिडियरी के बारे में:

पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी विविध एनर्जी मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिनमें: ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन; हाइड्रोजन ब्लेंडिंग; रिन्यूएबल एनर्जी (सोलर, विंड और हाइब्रिड); बायो-फ्यूल्स/बायो-गैस; और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) ऑपरेशन्स शामिल हैं।

ONGC और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा एक JV का गठन

23 जनवरी 2024 को आयोजित ONGC बोर्ड की बैठक के दौरान, बोर्ड ने या तो सीधे ONGC द्वारा या NTPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) के साथ इसकी सहयोगी/सब्सिडियरी के माध्यम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (JV) के गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

i.JVC ऑफशोर विंड एनर्जी और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी के व्यवसाय में लगी होगी।

ii.JVC का गठन NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया), निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) (वित्त मंत्रालय) सहित आवश्यक सरकारी/नियामक अनुमोदन के अधीन है।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ONGC) के बारे में:

ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को ऑयल & नेचुरल गैस कमीशन के रूप में की गई थी और यह MoP&NG के तहत एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

अध्यक्ष और CEO– अरुण कुमार सिंह

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली

भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में LOC के पास 'इंडिया सेल्फी पॉइंट' खोला

भारतीय सेना के डैगर डिवीजन (तत्कालीन 19वीं भारतीय इन्फैंट्री डिवीजन) ने जम्मू और कश्मीर (J&K) के बारामूला जिले में उरी में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास **'इंडिया सेल्फी पॉइंट'** खोला।

- यह सेल्फी पॉइंट प्रशंसित कलाकार रूबल नागी द्वारा उपहार में दिया गया है, जिन्होंने J&K में ऐसे कई पॉइंट स्थापित किए हैं।
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH 44) के किनारे स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और श्रीनगर (J&K) को कन्याकुमारी (तमिलनाडु) से जोड़ता है।
- सेल्फी प्वाइंट खोलने की यह पहल सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाने और एक ऐसा स्थान प्रदान करने की सेना की प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो वास्तव में वाइब्रेंट इंडिया की भावना से मेल खाता है।

STATE NEWS

दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया

दुर्गा शंकर मिश्रा को 1 जनवरी से 30 जून 2024 तक तीसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश (**UP**) के मुख्य सचिव **(CS)** के रूप में फिर से नियुक्त किया गया।

- 1984-बैच के UP कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी DS मिश्रा, जो शुरू में 31 दिसंबर, 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, को एक साल की सेवा विस्तार के साथ UP के CS के रूप में नियुक्त किया गया था।
- 30 दिसंबर 2022 को दूसरे विस्तार के बाद यह उनका तीसरा सेवा विस्तार था।

सुधांश पंत को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया

1991 बैच के IAS अधिकारी **सुधांश पंत** को **राजस्थान** का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने उषा शर्मा का स्थान लिया, जो 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुईं।

- उनके पास राजस्थान माइंस एंड मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी है।
- इस नियुक्ति से पहले, सुधांश पंत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया।

अतिरिक्त जानकारी:

1988 बैच के IAS अधिकारी अपूर्व चंद्रा को अतिरिक्त प्रभार के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में सूचना & प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

WB सरकार ने पोइला बैसाख को राज्य दिवस & टैगोर के बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया

पश्चिम बंगाल सरकार (WB) ने **पोइला बैसाख**, बंगाली नव वर्ष, को **राज्य दिवस** के रूप में घोषित किया और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की 1905 की बंगाल की कविता, **"बांग्लार माटी, बांग्लार जल"** (बंगाल की मिट्टी, बंगाल का पानी) को **राज्य गीत** के रूप में घोषित किया।

- राज्य दिवस को **"बांग्ला दिवस"** के रूप में मनाया जाएगा।

- पोइला बैसाख बंगाली कैलेंडर वर्ष के पहले महीने **बैसाख** महीने के **पहले दिन** मनाया जाता है, जो आमतौर पर **14 या 15 अप्रैल** को पड़ता है।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.राज्य दिवस हर साल पश्चिम बंगाल के सभी लोगों द्वारा सम्मान और गरिमा के साथ मनाया जाएगा।

ii.पश्चिम बंगाल में सभी आधिकारिक समारोहों की शुरुआत में 1 मिनट 59 सेकंड का राज्य गीत अनिवार्य रूप से बजाया जाएगा और समारोह के बाद राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बजाया जाएगा।

- जब राज्य गीत और राष्ट्रगान बजाया जाए तो सभी गणमान्य लोगों/व्यक्तियों को सावधान होकर खड़ा होना चाहिए और इसके सामूहिक गायन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि:

सितंबर 2023 में, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बंगाली कैलेंडर के पहले दिन, 'पोइला बैसाख' को राज्य दिवस के रूप में और रवींद्रनाथ टैगोर के गीत 'बांग्लार माटी बांग्लार जल' को राज्य गान घोषित करने का एक प्रस्ताव पारित किया।

- इसके बाद, राज्य मंत्रिमंडल ने विकास के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

नोट: यह आदेश पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव HK द्विवेदी द्वारा 30 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था, जो 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे।

बांग्लार माटी, बांग्लार जल के बारे में:

देशभक्ति गीत बांग्लार माटी, बांग्लार जल 1905 में वायसराय जॉर्ज नाथनियल कर्जन (1859-1925) के बंगाल विभाजन के संदर्भ में लिखा गया था।

- रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए बंगभंगा रोध आंदोलन के समर्थन में गीत लिखा था।

नोट: रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई बने।

बायु: असम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस शुरू की

असम राज्य परिवहन निगम (ASTC) ने असम के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वच्छ वायु आंदोलन **'बायु'** नामक एक पहल शुरू की है।

- यह भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक और विकेन्द्रीकृत ओपन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक बाइक (ई-बाइक) टैक्सी सर्विस है।
- ई-बाइक टैक्सी सर्विस की शुरुआत असम सरकार के परिवहन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने गुवाहाटी, असम में की।

बायु स्वच्छ वायु आंदोलन:

i.बायु स्वच्छ वायु आंदोलनअसम सरकार के परिवहन विभाग के नेतृत्व में गुवाहाटी स्थित **बिकोजी इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड** के सहयोग से ASTC द्वारा शुरू की गई एक स्थायी गतिशीलता पहल है।

ii.यह आंदोलन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग के **शून्य जीरो पॉलूशन मोबिलिटी** अभियान द्वारा समर्थित है।

iii.परिवहन और रसद क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों (**EV**) को तैनात करके, आंदोलन का उद्देश्य असम में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

iv.यह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (**ONDC**) पर तैनात किए जाने वाले डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए बेकन प्रोटोकॉल को भी लागू करता है।
v.यह आंदोलन स्थिरता, नवाचार और समावेशिता पर दृढ़ता से जोर देता है।
vi.यह आंदोलन ईंधन की बचत करके लगभग 29,000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है जिसकी लागत 73 करोड़ रुपये हो सकती है।

बायु द्वारा प्रदान की गई सर्विसेज:

i.बायू ASTC ने **'बायू राइडर'** नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।
ii.बायु ई-बाइक टैक्सी सर्विसेज, बिजनेस टू बिजनेस (**B2B**) फ्लीट सर्विसेज और हाइपरलोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रदान करता है।
iii.बायु तीन 'जीरो' मॉडल पर काम करती है।

- जीरो एमिशन
- जीरो कमीशन
- जीरो कैंसिलेशन

शून्य जीरो पॉलूशन मोबिलिटी अभियान:

i.शून्य जीरो पॉलूशन मोबिलिटी अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ सहयोग करके जीरो-पॉलूशन वितरण वाहनों को बढ़ावा देना है।
ii.यह अभियान NITI आयोग द्वारा सितंबर 2021 में शुरू किया गया था।

बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना: भारत का पहला 31-मीटर U-गर्डर सफलतापूर्वक डाला गया

6 जनवरी 2024 को, भारत में पहली बार, बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (BSRP) के लिए देवनहल्ली में कास्टिंग यार्ड में **31** मीटर, सिंगल-स्पैन U-गर्डर को सफलतापूर्वक डाला गया। अब तक, पूरे भारत में मेट्रो परियोजनाओं में 28-मीटर U-गर्डर्स का उपयोग किया गया है। पहली बार, BSRP ने 31 मीटर U गर्डर का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

- इन गर्डर्स का उपयोग हेब्बल से यशवंतपुर तक लगभग 8 km के वियाडक्ट (ऊंचे खंड) के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो BSRP की मल्लिगे लाइन या कॉरिडोर 2 का एक हिस्सा है।
- प्री-टेंशन्ड, प्रीकास्ट U गर्डर 69.5 क्यूबिक मीटर M60 ग्रेड कंक्रीट से बना है और इसका वजन 178 टन है। कॉरिडोर 2 के लिए ऐसे 450 U-गर्डर्स की जरूरत है।
- 31 मीटर U-गर्डर को BSRP के लिए एसिस्टम STUP (मुख्यालय दिल्ली में) द्वारा डिजाइन किया गया है और चेन्नई, तमिलनाडु में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास द्वारा प्रूफ-चेक किया गया है।

नोट: BSRP रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (K-राइड) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है।

WB CM ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में SC/ST छात्रों के लिए 'योग्यश्री' लॉन्च की

8 जनवरी, 2024 को, पश्चिम बंगाल (**WB**) की मुख्यमंत्री (**CM**) **ममता बनर्जी** ने कोलकाता, WB में एक कार्यक्रम के दौरान एक नई सामाजिक कल्याण योजना **'योग्यश्री'** लॉन्च की।
योग्यश्री विभिन्न प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति (**SC**) और अनुसूचित जनजाति (**ST**) के छात्रों के लिए एक मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल है।

- उन्होंने छात्रों के लिए एक टोल फ्री एंटी-रैगिंग नंबर भी पेश किया और एक छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया।

प्रमुख बिंदु:

i.योग्यश्री योजना के तहत पूरे राज्य में 50 केंद्र खोले जाएंगे जहां SC और ST छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से मुफ्त प्रशिक्षण ले सकेंगे।

ii.इसी तरह, 46 केंद्र सरकारी नौकरियों, सिविल सेवाओं आदि के इच्छुक छात्रों के लिए SC & ST छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

iii.अगस्त 2023 में, CM ममता बनर्जी ने पूरे WB में छात्रों के लिए 24/7 एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन शुरू की। हेल्पलाइन का नंबर 1800 345 5678 है।

पश्चिम बंगाल (WB) के बारे में:

मुख्यमंत्री–ममता बनर्जी

राज्यपाल– C. V. आनंद बोस

राष्ट्रीय उद्यान- सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान

वन्य जीवन अभ्यारण्य-जोरपोखरी वन्यजीव अभ्यारण्य, सेंचल वन्यजीव अभ्यारण्य

पंजाब मैपल्स में सभी दुर्घटना-संभावित स्थलों का मानचित्रण करने वाला पहला राज्य बन गया

पंजाब भारत का **पहला** राज्य बन गया है जिसने C. E. इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड (**MapmyIndia**) द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम मोबाइल एप्लिकेशन "**मैपल्स**" पर सभी 784 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप किया है।

- **पंजाब पुलिस** ने ब्लैक और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में मैपल्स ऐप पर वास्तविक समय के ट्रैफिक अपडेट और अलर्ट के लिए **MapmyIndia** के साथ सहयोग किया।
- यह घोषणा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने की।

प्रमुख बिंदु:

i.मैपल्स मोबाइल ऐप यात्रियों को आने वाले ब्लैक स्पॉट के बारे में वॉयस अलर्ट (**पंजाबी** भाषा में) प्रदान करेगा।

ii.इस पहल का उद्देश्य पंजाब की सड़कों पर यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना भी है।

iii.यह पहल पंजाब सरकार की प्रमुख परियोजना '**सड़क सुरक्षा बल**' के लॉन्च की तैयारियों का एक हिस्सा है।

मैपल्स:

i.मैपल्स लगभग 200 देशों को कवर करते हुए पूरी दुनिया के लिए विस्तृत मानचित्र प्रदान करता है; यह पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है।

ii.मैपल्स रियल-टाइम नेविगेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) ट्रैकिंग और लाइव ट्रैफिक अपडेट जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।

नोट-

दुर्घटना ब्लैकस्पॉट वह स्थान है जहां ऐतिहासिक रूप से सड़क यातायात दुर्घटनाएं केंद्रित रही हैं।

C. E इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में:

सह-संस्थापक– राकेश कुमार वर्मा और रश्मि वर्मा

अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक (CMD) – राकेश कुमार वर्मा

मुख्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली

स्थापित - 1995

पंजाब के बारे में:

मुख्यमंत्री - भगवंत सिंह मान

राज्यपाल – बनवारीलाल पुरोहित

वन्यजीव अभ्यारण्य - बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, बीर भुनेरहेरी वन्यजीव अभ्यारण्य

प्राणी उद्यान – महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान; टाइगर सफारी चिड़ियाघर

छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या की तीर्थयात्रा के लिए 'श्री रामलला दर्शन योजना' शुरू करेगी

मुख्यमंत्री (**CM**) विष्णु देव साई की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के लोगों को उत्तर प्रदेश (**UP**) के अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर की मुफ्त तीर्थयात्रा की पेशकश करने के लिए एक तीर्थयात्रा योजना '**श्री रामलला दर्शन योजना**' शुरू करने का निर्णय लिया है।

- **पात्रता**: छत्तीसगढ़ के मूल निवासी 18 से 75 वर्ष की आयु के लोग जो चिकित्सकीय रूप से फिट हैं, योजना के तहत पात्र हैं।
- इस योजना को छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और बजट पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (**IRCTC**) के सहयोग से संचालित किया जाएगा।
- इस योजना का लक्ष्य सालाना लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को रामलला के दर्शन कराना है।

नोट-

यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की जाएगी, जिस दिन रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह निर्धारित है।.

वीरा राणा को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया

मध्य प्रदेश (MP) सरकार ने 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी **वीरा राणा** को **MP का मुख्य सचिव (CS)** नियुक्त किया है।

- वह निर्मला बुच के बाद **MP की दूसरी महिला मुख्य सचिव** बनीं, जिन्होंने 1991-1993 तक MP की पहली महिला CS के रूप में कार्य किया।
- उन्हें MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.वह **इकबाल सिंह बैंस** के बाद **MP के कार्यवाहक CS** के रूप में कार्यरत हैं, जो नवंबर 2023 में पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

ii.वीरा राणा मार्च 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

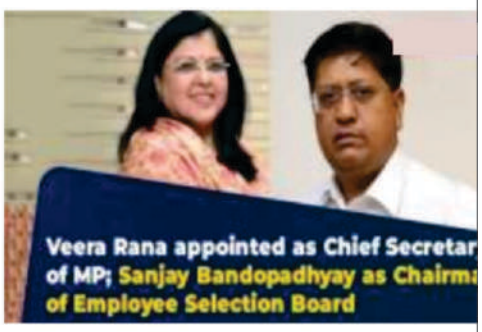

<u>वीरा राणा के बारे में:</u>

i.2023 में MP के कार्यवाहक CS के रूप में नियुक्ति से पहले, वह MPBSE के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं और MP के कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभालती थीं।

ii.उन्होंने पहले MP के विदिशा, जबलपुर और महासमुंद जिलों के कलेक्टर के रूप में कार्य किया है और प्रमुख विभागों में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई हैं।

संजय बंदोपाध्याय को एम्प्लोयी सेलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

MP सरकार ने MP कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी **संजय बंदोपाध्याय** को MP एम्प्लोयी सेलेक्शन बोर्ड **(MPESB)** (जिसे पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

- नियुक्ति से पहले, वह दिसंबर 2021 से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPS&W) के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

नोट:

i.मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति **(ACC)** ने IWAI के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय को उनके मूल कैडर में वापस भेजने को भी मंजूरी दे दी है।

ii.IWAI के उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह को IWAI के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

शरत चौहान केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए सचिव बने

29 जनवरी,2024 को, गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, **शरत चौहान,** प्रधान आयुक्त, वित्त, योजना और निवेश विभाग, अरुणाचल प्रदेश को तत्काल प्रभाव से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

i.वह AGMUT कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी राजीव वर्मा की जगह ले रहे हैं, और उन्हें चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार के रूप में तैनात किया गया है।

ii.चौहान 1994 AGMUT (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर से संबंधित हैं।

iii.उनके पिछले विभागों में निदेशक, उपायुक्त (परिवहन और पर्यटन, अंडमान जिला), निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य & सहयोग, चिकित्सा शिक्षा, प्रजनन & बाल स्वास्थ्य) और AIIMS में उप निदेशक शामिल हैं। उन्होंने आयुक्त-सह-सचिव के रूप में भी काम किया है। गोवा के मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के आयुक्त-सह-सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

iv.डॉ. चौहान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है।

पुडुचेरी के बारे में:–

मुख्यमंत्री - N.रंगास्वामी

राजधानी – पुडुचेरी

राज्यपाल – डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन

HP सरकार ने सरकारी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए 'माई स्कूल-माई प्राइड' अभियान शुरू किया

हिमाचल प्रदेश (**HP**) सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के अनुरूप **'अपना विद्यालय'** कार्यक्रम के तहत **'माई स्कूल-माई प्राइड'** अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

इस पहल का उद्देश्य स्कूलों को गोद लेने और छात्र विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करना है।

i.कार्यक्रम के तहत, 'गिविंग बैक टू सोसाइटी' पहल सेवानिवृत्त शिक्षकों, पेशेवरों, गृहिणियों, या किसी भी समुदाय के सदस्यों को स्वेच्छा से अकादमिक सहायता टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है।

ii.समग्र शिक्षा अभियान (SSA) गतिविधियों की पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा।

iii.इसमें 'व्यवस्थित किशोर प्रबंधन और मूल्य संवर्धन संवाद' (SAMVAD) घटक शामिल है, जो स्कूल जाने वाले किशोरों को नैतिक मूल्यों आदि के बारे में शिक्षित करता है।